website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक

रॉयल पत्रिका

वर्ष :13 | अंक : 255 | पेज: 8 | जयपुर, शनिवार 23 अगस्त 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 1 सितम्बर तक करेंगे जापान और चीन का दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितम्बर 2025 तक जापान और चीन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने आज शुक्रवार को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। इस यात्रा का पहला चरण जापान का होगा, जहां वे 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

जापान में पीएम मोदी का यह आठवां दौरा और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा। दोनों नेता भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। चर्चा में रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार, और जन-से-जन संबंध जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है।

वहीं यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक चीन के तियानजिन जाएंगे। यहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई सदस्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। भारत 2017 से SCO का सदस्य है और 2022-23 में संगठन की अध्यक्षता भी कर चुका है। यह दौरा भारत के पड़ोसी देशों और एशियाई साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- महिला शांति रक्षक बदलाव की मशाल

-UN मिशनों में उनकी भूमिका अहम

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महिला सैन्य अधिकारी पाठ्यक्रम (UNWMOC-2025) में भाग लेने वाली 15 देशों की महिला सैन्य अधिकारियों और 12 भारतीय महिला अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान रक्षामंत्री ने उन्हें वैश्विक शांति प्रयासों में "बदलाव की मशाल" करार दिया। यह पाठ्यक्रम 18 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) ने रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य महिला अधिकारियों की पेशेवर क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के नाते हमेशा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता रहा है। उन्होंने कहा, "हम अपनी सशस्त्र सेनाओं और शांति स्थापना दलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को मजबूत कर रहे हैं, ताकि उन्हें नेतृत्व और सेवा का समान अवसर मिल सके।" उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला अधिकारी शांति अभियानों में "अमूल्य दृष्टिकोण और अनोखा दृष्टिकोण" लेकर आती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के साथ भरोसा मजबूत होता है, यौन हिंसा की घटनाओं को रोका जा सकता है और मानवीय सहायता को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।

इस पाठ्यक्रम में आर्मेनिया, डीआर कांगो, मिस्र, आइवरी कोस्ट, केन्या, किर्गिज गणराज्य, लाइबेरिया, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, सिएरा लियोन, श्रीलंका, तंजानिया, उरुग्वे और वियतनाम की महिला अधिकारी हिस्सा ले रही हैं। इन अधिकारियों की मौजूदगी को राजनाथ सिंह ने "संयुक्त राष्ट्र की एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक" बताया।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने 'ब्लू हेलमेट ओडिसी : 75 ईयर्स ऑफ इंडियन पीसकीपिंग' शीर्षक वाली यूएन जर्नल 2025 का विमोचन भी किया, जो वैश्विक शांति में भारत के 75 वर्षों के योगदान को उजागर करता है। पाठ्यक्रम में आधुनिक शांति स्थापना से जुड़ी चुनौतियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, नागरिकों की सुरक्षा, शरणार्थियों के अधिकार, संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा और बच्चों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ड्यूटी के लिए नामित एक इन्फैंट्री बटालियन द्वारा फील्ड डेमोंस्ट्रेशन भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे।

रूस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ अन्य रूसी नेताओं, विद्वानों, उद्योगपतियों के साथ विदेश मंत्री जयशंकर की चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 19 से 21 अगस्त तक रूस का दौरा किया और भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस दौरे में उन्होंने रूसी नेताओं, विद्वानों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता साफ हुआ।

विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की

19 अगस्त को विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया और द्विपक्षीय एजेंडे के साथ-साथ यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया, जो संबंधों को और मजबूत करने में सहायक होगा।

आईआरआईजीसी-टीईसी के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की

20 अगस्त को डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ आईआरआईजीसी-टीईसी के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस सत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को हटाने, लॉजिस्टिक्स में सुधार, कनेक्टिविटी बढ़ाने, भुगतान प्रणाली को आसान बनाने और 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लागू करने की योजना पर चर्चा की।

द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

इसके अलावा, भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ के मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नियमित संपर्क बढ़ाने पर सहमति बनी। लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। सत्र के अंत में दोनों सह-अध्यक्षों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। सत्र में ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने और भारतीय कुशल श्रमिकों, खासकर आईटी, निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उनकी गतिशीलता पर भी ध्यान दिया गया। इससे दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

विदेश मंत्री और मंटुरोव ने मंच को संबोधित किया

आईआरआईजीसी-टीईसी सत्र के बाद आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच में अधिकारियों, व्यवसायियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विदेश मंत्री और मंटुरोव ने इस मंच को संबोधित किया। दोनों पक्षों ने व्यापार मंच और आईआरआईजीसी के कार्य समूहों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो भविष्य में सहयोग को और प्रभावी बनाएगा।

डॉ. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात

21 अगस्त को डॉ. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत-रूस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सैन्य-तकनीकी सहयोग और कजान व येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों के उद्घाटन को तेज करना शामिल था। वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों ने जी20, ब्रिक्स और एससीओ में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अपनी प्रतिबद्धता जताई।

भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी कटौती नीति दोहराई

यूक्रेन, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने संवाद और कूटनीति को विवाद सुलझाने का जरिया बताया। उन्होंने रूसी सेना में काम करने वाले भारतीयों के मामलों के शीघ्र समाधान की उम्मीद भी जताई। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने मिलकर लड़ने का संकल्प लिया और भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी कटौती नीति दोहराई।

दोनों पक्षों ने अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने लावरोव को भारत आने का निमंत्रण दिया।

भारत का अपना स्पेस स्टेशन : ISRO ने दिखाया मॉडल, 2028 तक लॉन्च होगा पहला मॉड्यूल

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को देश के पहले स्पेस स्टेशन का मॉडल प्रदर्शित किया। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे से ठीक पहले राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इस मॉडल को दिखाया गया। भारत 2028 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)' का पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है।

फिलहाल पूरी दुनिया में केवल दो ऑर्बिटल लेबोरेटरी मौजूद हैं – पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जिसे अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप मिलकर चला रहे हैं, और दूसरा चीन का तियांगोंग स्टेशन। अब भारत तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन होगा।

2035 तक 5 मॉड्यूल भेजने का लक्ष्य

भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक कुल 5 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएं। पहला मॉड्यूल BAS-01 लगभग 10 टन का होगा और इसे 450 किलोमीटर ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा।

रिसर्च, मेडिकल और स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा

BAS में लाइफ साइंस, मेडिसिन और ग्रहों की खोज से जुड़ी रिसर्च होगी।

•माइक्रोग्रैविटी में इंसानों की सेहत पर असर का अध्ययन
•लंबे समय तक स्पेस में रहने की तकनीक पर रिसर्च
•बीज और माइक्रोएल्गी जैसे प्रयोग
•भविष्य में स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा

इससे भारत को कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में नई पहचान मिलेगी।

गगनयान और चंद्र मिशन

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा और इसे 'भारत अंतरिक्ष स्टेशन' नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 2040 तक भारत एक एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने की योजना पर काम कर रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि गगनयान मिशन के तहत 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। इसके अलावा भारत डीप ओशन मिशन के तहत 6,000 मीटर गहराई तक मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है।

भारतीय एस्ट्रोनॉट का ISS अनुभव

भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक्सियम-4 मिशन के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। वे वहां 18 दिन रहे और 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। इस दौरान उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया, जिनमें 7 प्रयोग भारत के थे।

•अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज उगाए
•स्पेस माइक्रोएल्गी प्रयोग किया
•हड्डियों की सेहत पर रिसर्च की

28 जून 2025 को शुक्ला ने ISS से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया था। भारतीय स्पेस स्टेशन का मॉडल देखकर यह साफ है कि भारत अब केवल अंतरिक्ष तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाने वाला देश बनने जा रहा है।

'वैक्सीनेशन के बाद अब आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा' - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके।

कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।

तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। अपने फैसले में कहा, "बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।"

हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी, 338 सड़कें बंद, जनजीवन प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के राज्य आपात संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार पिछले 24 घंटों में 338 सड़कें, 132 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (डीटीआर) और 141 जलापूर्ति योजनाएं ठप हो गई हैं।

शुक्रवार की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक एनएच-305 कई स्थानों- बालीचौकी, गजाधार पर बंद है, जबकि वैकल्पिक रास्ते भी बाधित हो गए हैं। वहीं मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 165 सड़कें बंद हैं, इसके बाद कुल्लू (123) और कांगड़ा (21) का स्थान है।

बिजली आपूर्ति के मामले में कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 77 डीटीआर ठप हो गए हैं, जबकि मंडी में 54 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कांगड़ा में आठ जल योजनाएं ठप हैं और धर्मशाला, नूरपुर और देहरा उपमंडलों में बिजली बहाली का काम जारी है। राहत और बहाली के लिए सड़क साफ करने वाली टीमें, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। इस मानसून सीजन में राज्य में अब तक कई जनहानि, सैकड़ो मकानों को नुकसान और फसलों, बागवानी और सार्वजनिक ढांचे को भारी क्षति हुई है। एसडीएमए के अनुसार अब तक का कुल वित्तीय नुकसान 2,28,226.86 लाख रुपये से अधिक आंका गया है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बहाली का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश और नए भूस्खलन की आशंका से काम में दिक्कतें आ रही हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, कुल भंडार 695.11 अरब डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह आंकड़ा 15 अगस्त को बढ़कर 695.11 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी गई। पिछले सप्ताह 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.75 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे भंडार 693.62 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लगातार वृद्धि से भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति की मजबूती का संकेत है।

गौरतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि से RBI के पास अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये को स्थिर रखने की अधिक क्षमता मिलती है। पर्याप्त भंडार से RBI स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसी मार्केट में डॉलर छोड़कर रुपये की तेज गिरावट को रोक सकता है और उसकी अस्थिरता को नियंत्रित कर सकता है। 15 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेन करेंसी एसेट्स (Foreign Currency Assets), जो रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, 1.92 अरब डॉलर बढ़कर 585.9 अरब डॉलर हो गए। डॉलर में व्यक्त ये एसेट्स यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं की विनिमय दर में बदलाव से भी प्रभावित होते हैं।

वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 85.67 अरब डॉलर पर रहा। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने सोने को सुरक्षित निवेश मानते हुए भंडारण बढ़ाया है। आरबीआई द्वारा रखे गए सोने का हिस्सा 2021 के बाद से लगभग दोगुना हो गया है। विशेष आहरण अधिकार 18.78 अरब डॉलर पर बने हुए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक के आयात और लगभग 96 प्रतिशत बाहरी ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा, "भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और सभी प्रमुख संकेतक सुधार की ओर हैं। हमें अपने बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।"

इस बीच, जुलाई 2025 में भारत के निर्यात में 7.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 34.71 अरब डॉलर से बढ़कर 37.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि जुलाई और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सेवाओं और माल निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वैश्विक निर्यात वृद्धि दर से कहीं अधिक है। जुलाई में निर्यात के प्रमुख क्षेत्र इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, रसायन, रत्न और आभूषण रहे।

दिल्ली-एनसीआर में पल-पल बदल रहा मौसम

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम हर पल नया रंग दिखा रहा है। सुबह की तेज धूप दोपहर तक घने बादलों और बारिश में बदल रही है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 22 से 27 अगस्त तक एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

22 और 26 अगस्त को आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका

22 और 26 अगस्त को आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश, जबकि 23, 24 और 25 अगस्त को मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। 27 अगस्त तक रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

बदलते मौसम से जनजीवन प्रभावित

हर दो घंटे में मौसम के बदलने से लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। सुबह धूप में घर से निकलने वाले लोग अचानक बारिश और काले बादलों का सामना कर रहे हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जलभराव की स्थिति आम हो गई है।

बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार

बारिश का एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। लगातार वर्षा ने दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को उत्तम श्रेणी में ला दिया है। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व धुलने से शुद्ध हवा मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त की बारिश ने प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया है, जो सामान्य दिनों में खराब से बहुत खराब रहता था।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

दंड प्रणाली में बदलाव की दिशा में सराहनीय पहल

दंड प्रणाली में बदलाव की दिशा में उठाया जा रहा कदम वास्तव में सराहनीय है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारी न्याय और दंड प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं, लेकिन ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से अभी भी इसमें व्यापक बदलाव की गुंजाइश बनी हुई है। जेलों की मौजूदा स्थिति इस बात की गवाही देती है कि हमारे कानून और दंड प्रणाली में कहीं न कहीं संतुलन का अभाव है। देश की जेलों में उनकी क्षमता से बीस से तीस प्रतिशत अधिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो छोटे-मोटे अपराधों के कारण जेल की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे मामलों में लंबे समय तक जेल में रखने से न तो अपराध घटता है और न ही समाज को कोई बड़ा लाभ होता है, बल्कि उल्टा जेलों में भीड़ बढ़ने से व्यवस्था पर दबाव और कैदियों के सुधार की संभावना कम हो जाती है। इसी पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार का जन विश्वास (संशोधन) विधेयक एक क्रांतिकारी पहल के रूप में सामने आता है। इस विधेयक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह छोटे अपराधों के लिए जेल की सज़ा की जगह जुर्माने का प्रावधान करता है। यह बदलाव दो स्तरों पर प्रभावी हो सकता है। पहला, इससे जेलों में भीड़ घटेगी और व्यवस्थागत दबाव कम होगा। दूसरा, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी बड़ी कमी आएगी। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार जुलाई 2023 तक देश में 4.4 करोड़ मामले लंबित थे जिनमें 3.3 करोड़ आपराधिक मामले थे। ऐसे में अगर छोटे अपराधों को जुर्माने या चेतावनी जैसी सज़ा में बदला जाता है तो अदालतों पर से बोझ 20 से 30 प्रतिशत तक घट सकता है। यह न्याय व्यवस्था को गति देने और पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कई कानून ऐसे हैं जो आज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुके हैं, फिर भी उनके तहत मुकदमे चलते रहते हैं। इससे न केवल अदालतों का बोझ बढ़ता है बल्कि आम नागरिकों और व्यापारियों को भी बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे गैरज़रूरी मामलों से राहत दिलाना है ताकि न्यायिक व्यवस्था की ऊर्जा और समय गंभीर अपराधों और ज़रूरी मामलों में लगाया जा सके। विधेयक के प्रावधानों में यह बात भी उल्लेखनीय है कि 76 मामलों में पहली बार उल्लंघन पर केवल चेतावनी या सलाह देने का प्रावधान किया गया है। यह दृष्टिकोण दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक न्याय की ओर बढ़ने का प्रतीक है। छोटे उल्लंघनों में सीधे जेल भेजने या भारी सज़ा देने से व्यक्ति के जीवन पर स्थायी नकारात्मक असर पड़ सकता है, जबकि चेतावनी और सलाह उसे सुधारने का अवसर देती है। इस तरह यह विधेयक केवल दंड को कम करने की दिशा में नहीं बल्कि सुधार की सोच को आगे बढ़ाने वाला है।

स्लैब में बदलाव : नए सुधारों का मकसद मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों पर कर बोझ घटाना

-डिजिटल ट्रांजैक्शन और जीएसटी का रिश्ता

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 को संसद के विशेष मध्यरात्रि सत्र में लागू किया गया था। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य था कि देश भर में फैली जटिल और बिखरी हुई कर प्रणाली को एकीकृत किया जाए और उपभोक्ता से लेकर उद्योग तक हर किसी को एक पारदर्शी, सरल और एक राष्ट्र–एक कर की व्यवस्था मिले। जीएसटी के आठ साल पूरे होने के बाद अब समय आ गया है कि इसके स्लैब और दरों में बदलाव कर मध्यम वर्ग, छोटे उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। सरकार भी मान रही है कि वर्तमान ढांचा कहीं-कहीं भारी साबित हो रहा है, विशेषकर जब महंगाई और बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं।

जीएसटी की पृष्ठभूमि और महत्व

जीएसटी से पहले की स्थिति

केंद्र सरकार: उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क आदि। राज्य सरकारें: वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी, प्रवेश कर आदि। अलग-अलग दरों और कानूनों से व्यापारियों और उद्योगों को भारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता था।

जीएसटी लागू होने के बाद

इन सभी करों को समाहित कर एक साझा राष्ट्रीय कर प्रणाली बनी। उपभोक्ता स्तर पर करों की पारदर्शिता बढ़ी। ई-वे बिल और जीएसटीएन पोर्टल जैसी डिजिटल व्यवस्था ने कर चोरी रोकने में मदद की। राज्यों को शुरुआती पाँच वर्षों तक राजस्व हानि की भरपाई का आश्वासन दिया गया।

जीएसटी की उपलब्धियाँ

एकीकृत बाजार का निर्माण : अब कोई राज्य की सीमा पार करने पर चुंगी या अलग कर नहीं। ईमानदार करदाता को फायदा : इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) व्यवस्था ने दोहरे कराधान को रोका। डिजिटल सुधार : ऑनलाइन रिटर्न, ई-इनवॉइसिंग और ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार घटा। राजस्व संग्रह : प्रारंभिक झटकों के बावजूद धीरे-धीरे जीएसटी संग्रह लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

समस्याएँ और चुनौतियाँ

जटिल स्लैब संरचना : 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की पाँच प्रमुख दरों के अलावा कई अपवाद और सेस। छोटे उद्योगों पर बोझ : कम्प्लायंस का दबाव, बार-बार रिटर्न और तकनीकी कठिनाइयाँ। राज्यों की चिंता : 2022 के बाद क्षतिपूर्ति प्रावधान समाप्त होने से कई राज्यों को घाटे का डर। मध्यम वर्ग पर असर : आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी कभी-कभी ऊँची दरें लागू हो जाती हैं। कर चोरी और फर्जी बिलिंग : सख्ती के बावजूद अभी भी व्यापक समस्या।

स्लैब में बदलाव की ज़रूरत क्यों? महंगाई से राहत : 5% और 12% की दरों पर आने वाले सामान आम जनता की ज़रूरत से जुड़े हैं। इन्हें सरल बनाकर जीवनयापन सस्ता हो सकता है। उद्योगों को बढ़ावा : छोटे और मध्यम उद्योग (MSME) ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं। दरें कम करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। रोज़गार पर असर : MSME सेक्टर रोजगार का बड़ा स्रोत है। कर राहत मिलने पर रोजगार बढ़ेगा। कर अनुपालन आसान : स्लैब घटाकर तीन करना (जैसे – 5%, 15%, 25%) से पारदर्शिता और सरलता आएगी।

प्रस्तावित सुधार और नए सुझाव

स्लैब संरचना में कमी : पाँच के बजाय तीन दरें। मूलभूत वस्तुएँ : दाल, चावल, दूध, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ 0% या 5% पर बनी रहें। मध्यम वर्ग की ज़रूरतें : कपड़े, जूते, घरेलू उपकरण 12% से घटाकर 8–10% पर लाए जाएँ। लक्ज़री और पाप कर : तंबाकू, शराब, पेट्रोलियम पर उच्च दर बनाए रखें। डिजिटल और MSME प्रोत्साहन : छोटे कारोबारियों को छूट, सरल रिटर्न और तिमाही भुगतान की सुविधा।

राज्यों की चिंताएँ और समाधान राज्यों को डर है कि कर दरें घटाने से उनका राजस्व कम होगा।

संभावित समाधान : केंद्र द्वारा विशेष सहायता कोष। डिजिटल कर प्रशासन से कर आधार (Tax Base) बढ़ाना। कर चोरी पर सख्ती। पेट्रोलियम और शराब को जीएसटी दायरे में लाने पर विचार।

मध्यम वर्ग पर असर

घरेलू बजट पर राहत। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर और छोटे उपकरण सस्ते। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कम कर। किराए और गृह ऋण से जुड़ी सेवाओं पर भी राहत संभव।

उद्योग और रोजगार पर प्रभाव उत्पादन लागत घटेगी। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर को प्रोत्साहन। MSME क्षेत्र में निवेश और रोजगार में वृद्धि।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

यूरोपीय यूनियन : वहाँ VAT प्रणाली सरल और एकरूप है। सिंगापुर और मलेशिया : सीमित स्लैब, जिससे कारोबारियों के लिए आसान। भारत को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दरों को सरल करना होगा।

भविष्य की दिशा

एक राष्ट्र, एक कर, एक स्लैब की ओर बढ़ना। डिजिटल इंडिया और जीएसटी 2.0 का आगमन। राज्यों को स्थायी राजस्व सुनिश्चित करने की नीति। उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए संतुलन साधना। जीएसटी की यात्रा अब तक कई उपलब्धियों और चुनौतियों से भरी रही है। आठ साल बाद यह स्पष्ट है कि अब अगला कदम स्लैब सुधार होना चाहिए। मध्यम वर्ग और छोटे उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि उनके ऊपर कर का बोझ घटाया जाएगा तो उपभोग बढ़ेगा, उत्पादन तेज़ होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्लैब में बदलाव सिर्फ कर सुधार नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम होगा। राज्यों और केंद्र को मिलकर ऐसा संतुलित समाधान निकालना होगा, जिससे न केवल राजस्व सुरक्षित रहे, बल्कि जनता को भी वास्तविक लाभ मिले। भारत में जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दायरे से बाहर है। स्लैब सुधार का एक मकसद यह भी होना चाहिए कि कम दरों के जरिए अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से कर प्रणाली में शामिल हों। जब कर का बोझ हल्का लगेगा तो कर चोरी की प्रवृत्ति भी घटेगी।

डिजिटल ट्रांजैक्शन और जीएसटी

नोटबंदी और जीएसटी के बाद डिजिटल लेन-देन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सरकार के पास अब हर बिक्री और हर रसीद का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। स्लैब सुधार और डिजिटलीकरण साथ-साथ चलें तो कर संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्यों की राजस्व हानि की भरपाई भी आसान होगी। MSME उद्योगों का कहना है कि उन्हें बड़े उद्योगों की तरह पेशेवर एकाउंटिंग स्टाफ नहीं मिल पाता। जटिल स्लैब और नियमों के कारण उनका ध्यान उत्पादन की बजाय कागजी औपचारिकताओं पर चला जाता है। अगर स्लैब सरल किए जाएँ और रिटर्न फाइलिंग को तिमाही या अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो उनका बोझ घटेगा और वे प्रतिस्पर्धा में टिक पाएँगे।

उपभोक्ताओं की उम्मीदें

मध्यम वर्ग लंबे समय से यह मांग करता आ रहा है कि रोजमर्रा की वस्तुओं को 5% से अधिक पर टैक्स न लगे। रसोई से जुड़ी वस्तुओं पर तो राहत मिली है, लेकिन कपड़े, जूते, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू सामानों पर टैक्स दरें ऊँची हैं। स्लैब सुधार से यह वर्ग सीधा लाभान्वित होगा और उपभोग भी बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। स्लैब सुधार न केवल कर नीति का मुद्दा है बल्कि यह भारत की आर्थिक विकास रणनीति का अहम हिस्सा भी है। यदि सरकार समय रहते यह कदम उठाती है तो जीएसटी अपनी मूल भावना — एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार — को सच में मजबूत कर पाएगा। यह सुधार भारत को न केवल निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगा बल्कि नागरिकों के लिए भी राहत का सबब बनेगा।

बिना पाठ्यपुस्तकों के पढ़ाई: बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

- सरकारी दावे और जमीनी सच्चाई

शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है। यही वह साधन है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ न सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए बेहतर भविष्य गढ़ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षा के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत – किताबें – ही समय पर बच्चों तक नहीं पहुँचतीं, तो उस भविष्य का क्या होगा? राजस्थान जैसे बड़े और शैक्षिक रूप से संघर्षरत राज्य में हालात यह हैं कि शिक्षा सत्र शुरू हुए महीनों गुजर जाने के बाद भी कक्षा 1 से 6 तक की पाठ्यपुस्तकें व वर्कबुक कई स्कूलों में नहीं पहुँची हैं। सरकारी दावों और हकीकत के बीच यह खाई बच्चों की पढ़ाई को सीधे-सीधे प्रभावित कर रही है।

सरकारी दावे बनाम जमीनी सच्चाई

शिक्षा विभाग और सरकार का दावा है कि किताबें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती हैं और स्कूलों में प्रिंटर मौजूद हैं। लेकिन यह दावा हकीकत से बहुत दूर है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की समस्या: अधिकांश स्कूलों में इंटरनेट या तो है ही नहीं या बेहद कमजोर है। शिक्षक डाउनलोड करने की स्थिति में ही नहीं हैं। प्रिंटर की कमी: अधिकतर स्कूलों में प्रिंटर नहीं हैं। जहाँ हैं, वहाँ इंक व पेपर की व्यवस्था नहीं है। वर्कबुक की अनुपलब्धता: किताबें मान लीजिए किसी तरह डाउनलोड हो भी जाएँ, लेकिन वर्कबुक बच्चों के अभ्यास का मुख्य साधन होती हैं। इनके बिना बच्चे सीखे हुए को दोहराने और समझने में पिछड़ जाते हैं। यानी सरकार के दावे कागजों तक ही सीमित हैं, जबकि ज़मीन पर बच्चों का कोर्स अधूरा है।

शिक्षा सत्र का बिगड़ता संतुलन

राजस्थान के शिविरा पंचांग के अनुसार सितंबर में प्रथम टेस्ट निर्धारित हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब किताबें ही नहीं पहुँचीं, तो शिक्षक कोर्स पूरा कैसे कराएँगे? शिक्षकों के सामने पढ़ाई और परीक्षा दोनों का संकट है। बच्चों की बुनियाद कमजोर हो रही है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना तो दूर, बच्चों के लिए यह समझना भी मुश्किल हो रहा है कि उन्हें पढ़ना क्या है। यह सीधे-सीधे शिक्षा सत्र के संतुलन को बिगाड़ रहा है।

सरकारी योजनाओं की विफलता का उदाहरण

सरकारें अकसर कल्याणकारी योजनाओं का खूब ढिंढोरा पीटती हैं। "बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलेंगी" भी ऐसी ही योजना है। लेकिन हकीकत यह है कि – योजना बनी तो, लेकिन वितरण प्रणाली ध्वस्त है। किताबें छपने के बावजूद समय पर स्कूलों तक नहीं पहुँचीं। कई बार ठेकेदारी प्रबंधन में गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। शिक्षा विभाग गैर-शैक्षिक कार्यों – जैसे 'जियो टैगिंग' और आंकड़े इकट्ठा करने – में उलझा हुआ है। इससे यह साफ होता है कि प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई नहीं, बल्कि विभागीय औपचारिकताएँ हैं।

सरकारी बनाम निजी स्कूल: एक असमानता

निजी स्कूलों के बच्चों के पास विकल्प होते हैं – किताबें और गाइड ख़रीदने की क्षमता। ऑनलाइन साधनों का सहारा। ट्यूशन और अतिरिक्त क्लास की सुविधा। लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास केवल सरकारी किताबें और वर्कबुक ही सहारा होती हैं। जब यही समय पर न मिलें तो उनका भविष्य सीधे प्रभावित होता है। इस असमानता से समाज में पहले से मौजूद शिक्षा की खाई और चौड़ी हो रही है।

बच्चों के भविष्य पर असर

बिना किताबों और वर्कबुक के पढ़ाई का असर सिर्फ़ आज की पढ़ाई पर नहीं, बल्कि बच्चों के पूरे भविष्य पर पड़ता है। बुनियादी ज्ञान की कमी: शुरुआती कक्षाओं की किताबें बच्चों की नींव मजबूत करती हैं। इनके बिना गणित, भाषा और विज्ञान जैसी बुनियादी समझ अधूरी रह जाती है। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना: सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में वैसे ही निजी स्कूलों के छात्रों से पिछड़ते हैं। अब बिना किताबों के वे और पीछे छूट जाएंगे। मानसिक दबाव: जब बच्चे कोर्स पूरा नहीं कर पाते, तो टेस्ट और परीक्षाओं में कमजोर प्रदर्शन करते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास

की कमी और मानसिक दबाव बढ़ता है। ड्रॉपआउट दर में बढ़ोतरी: जब बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं तो कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह स्थिति पूरे समाज के लिए खतरनाक है।

शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं पर सवाल

आज विभाग का ज़्यादा ध्यान किताबें पहुँचाने पर नहीं बल्कि जियो टैगिंग, निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने पर है। जबकि शिक्षा का पहला काम यही होना चाहिए कि – बच्चों को समय पर किताबें मिलें। स्कूल भवन सुरक्षित हों। शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान दें, न कि गैर-शैक्षणिक कार्यों में उलझे रहें।

ग्रामीण इलाकों की दुश्वारियाँ

ग्रामीण इलाकों के स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के पास इंटरनेट और मोबाइल उपलब्ध नहीं। घर में पढ़ाई के लिए न किताब, न कॉपी, न गाइड। शिक्षक भी सीमित संसाधनों के कारण पढ़ाई कराने में असमर्थ। परिवार आर्थिक रूप से किताबें खरीदने में सक्षम नहीं। इससे ग्रामीण बच्चों और शहरी बच्चों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है।

समस्या की जड़ कहाँ है?

प्रशासनिक लापरवाही: छपाई व वितरण समय पर न होना। ठेकेदारी प्रबंधन: प्राइवेट ठेकेदारों को किताबें पहुँचाने की जिम्मेदारी, लेकिन कोई सख्त जवाबदेही नहीं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: चुनावी घोषणाओं में शिक्षा को महत्व, लेकिन व्यावहारिक कार्यान्वयन में उदासीनता। निगरानी की कमी: विभाग के अधिकारी फील्ड विज़िट नहीं करते।

समाधान और सुझाव

किताब वितरण की ठोस नीति: किताबें छपने से पहले ही वितरण का टाइम टेबल तय हो। हर जिले में कंट्रोल रूम बने जो समय पर किताबें पहुँचने की निगरानी करे। डिजिटल विकल्प का असली इस्तेमाल: ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट और प्रिंटर की सुविधा दी जाए। शिक्षक को प्रिंटिंग व स्टेशनरी का बजट मिले।

वर्कबुक की अनिवार्यता: सिर्फ किताबें ही नहीं, वर्कबुक भी बच्चों तक समय पर पहुँचे। बिना वर्कबुक के अभ्यास अधूरा रहेगा। जिम्मेदारी तय हो: समय पर किताबें न पहुँचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ठेकेदारों के खिलाफ पेनल्टी और ब्लैकलिस्टिंग की व्यवस्था हो। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए: ताकि वे बच्चों को पढ़ाने पर फोकस कर सकें। बच्चों का भविष्य किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी ज़िम्मेदारी ही सरकार और विभाग ठीक से नहीं निभा पाते, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि किताबों और वर्कबुक की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। क्योंकि यह सिर्फ एक योजना या वितरण प्रक्रिया नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। बिना किताबों के पढ़ाई करवाना बच्चों के साथ नाइंसाफी है और उनके भविष्य के साथ खुला खिलवाड़। अगर सरकार और विभाग अब भी नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियाँ न केवल पढ़ाई में पिछड़ेंगी, बल्कि समाज में असमानता और भी गहरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग को ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हर बच्चा समय पर किताबें पाकर अपने सपनों की उड़ान भर सके।

बेग़म हज़रत महल : लखनऊ की शेरनी और 1857 की क्रांति की वीरांगना

भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित और व्यापक विद्रोह सन 1857 की बग़ावत थी। इस क्रांति ने न केवल अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव हिला दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय स्त्रियाँ भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थीं बेग़म हज़रत महल, जो नवाब वाजिद अली शाह की बेग़म थीं और जिन्होंने लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का अद्‌भुत परिचय दिया। उन्हें भारतीय इतिहास में 'लखनऊ की शेरनी' कहा जाता है।

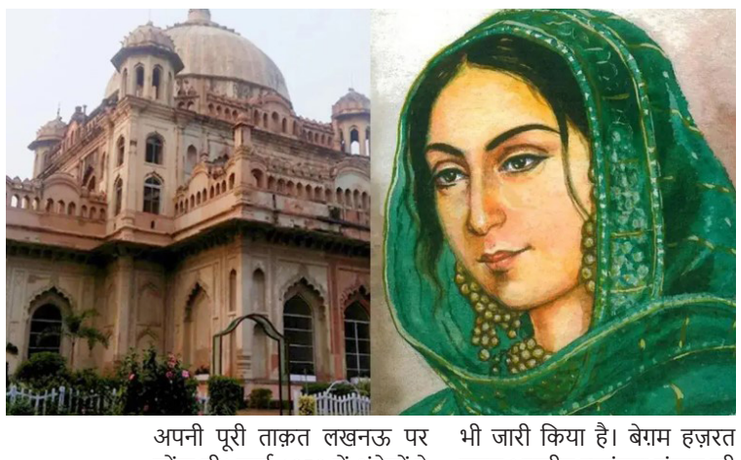

प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

बेग़म हज़रत महल का जन्म 1820 के आसपास हुआ। उनका असली नाम मुहम्मदी ख़ातून था। वे सामान्य पृष्ठभूमि से आई थीं और बचपन में उन्हें नवाब वाजिद अली शाह के शाही हरम में जगह मिली। बाद में वे उनकी पसंदीदा बेग़मों में शामिल हुईं। उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक आकर्षण, दृढ़ इच्छाशक्ति और राजनीतिक समझ थी, जो आगे चलकर उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित करती है। नवाब वाजिद अली शाह कला, साहित्य और संगीत के बड़े प्रशंसक थे। वे शासन की अपेक्षा शायरी, नृत्य और अदब की दुनिया में अधिक मशगूल रहते थे। इस कारण से अंग्रेज़ों ने उन्हें शासन के योग्य नहीं माना और सन 1856 में उन्हें सत्ता से हटाकर कलकत्ता (अब कोलकाता) निर्वासित कर दिया। यह घटना अवध (लखनऊ) की जनता के लिए गहरी चोट थी। ऐसे कठिन समय में बेग़म हज़रत महल ने नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में ली।

1857 की बग़ावत और लखनऊ

जब 1857 में सैनिक विद्रोह भड़का, तो उसकी चिंगारी मेरठ से निकलकर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। अवध की जनता पहले से ही अंग्रेज़ों की नीतियों से नाराज़ थी। किसानों पर लगान का बोझ, तालुकेदारों की ज़मीनें छीने जाना और नवाब की बेइज़्ज़ती – ये सब वजहें जनता के गुस्से को भड़काने के लिए काफी थीं। इसी माहौल में बेग़म हज़रत महल ने बाग़ियों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस क़द्र को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं पर्दे के पीछे से सत्ता संचालन शुरू किया।

संघर्ष और नेतृत्व

बेग़म हज़रत महल ने लखनऊ में बाग़ियों और जनता को एकजुट किया। उन्होंने सैनिकों, तालुकेदारों और किसानों को प्रेरित किया कि अंग्रेज़ों को हर कीमत पर भगाना है। किला और दरबार का संगठन – उन्होंने लखनऊ के क़िले को बाग़ियों का मज़बूत गढ़ बनाया। बिरजिस क़द्र का राज्याभिषेक – अपने बेटे को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने जनता को यह संदेश दिया कि अवध की सत्ता अभी भी उनकी है, अंग्रेज़ सिर्फ़ गैर-क़ानूनी कब्ज़ेदार हैं। जनसमर्थन – उन्होंने आम जनता और धार्मिक नेताओं से अपील की कि वे इस संघर्ष में हिस्सा लें। उनकी अपील का असर हुआ और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए। हज़रत महल ने न केवल सेना की अगुवाई की बल्कि युद्ध की रणनीति बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जंग

लखनऊ की धरती पर 1857 की क्रांति के दौरान भयंकर युद्ध लड़े गए। बेग़म हज़रत महल की सेनाओं ने अंग्रेज़ों को कई बार चुनौती दी। रेज़ीडेंसी (अंग्रेज़ों का मुख्य ठिकाना) पर लंबे समय तक घेराबंदी रखी गई। अंग्रेज़ सैनिक महीनों तक घिरे रहे। हालाँकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और बेहतर संसाधन थे, फिर भी बेग़म हज़रत महल और उनके सहयोगियों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। लखनऊ की गलियों, किलों और बाग़-बग़ीचों में खून-खराबा हुआ। अंततः अंग्रेज़ों ने दिल्ली और कानपुर पर कब्ज़ा करने के बाद अपनी पूरी ताक़त लखनऊ पर झोंक दी। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को पुनः जीत लिया।

पराजय और निर्वासन

लखनऊ के पतन के बाद भी बेग़म हज़रत महल हार मानने वालों में से नहीं थीं। वे अवध छोड़कर नेपाल चली गईं। नेपाल के शासक जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। वहाँ रहते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाना जारी रखा। उन्होंने नेपाल से घोषणाएँ जारी कीं जिनमें अंग्रेज़ों की नीतियों की निंदा की गई और भारतीय जनता से आग्रह किया गया कि वे अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखें।

लेकिन धीरे-धीरे संसाधनों की कमी और निरंतर निर्वासन की ज़िंदगी ने उनके संघर्ष को कमज़ोर कर दिया।

निधन

बेग़म हज़रत महल का निधन 1879 में नेपाल में हुआ। वे वहीं दफ़नाई गईं। उनकी कब्र आज भी काठमांडू में मौजूद है।

बेग़म हज़रत महल की विरासत

महिला नेतृत्व का प्रतीक – उन्होंने दिखाया कि स्त्रियाँ भी कठिन से कठिन हालात में नेतृत्व कर सकती हैं। स्वाभिमान और साहस – अंग्रेज़ों की ताक़त और संसाधनों के बावजूद उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। धर्मनिरपेक्ष सोच – उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सभी को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। उनके योगदान को याद करने के लिए लखनऊ में हज़रत महल पार्क बनाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। बेग़म हज़रत महल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान योद्धा थीं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि औरतें केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए युद्धभूमि में भी डट सकती हैं। उनकी ज़िंदगी त्याग, संघर्ष और साहस का अद्वितीय उदाहरण है।

अगर आज़ादी की पहली लड़ाई की वीरांगनाओं का ज़िक्र किया जाए, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बेग़म हज़रत महल का नाम भी गर्व से लिया जाता है। उन्होंने लखनऊ की गलियों में बहादुरी की जो मिसाल कायम की, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। बेग़म हज़रत महल केवल एक योद्धा ही नहीं थीं, बल्कि वे जनता के दुख-दर्द को गहराई से समझने वाली शासक भी थीं। उन्होंने अंग्रेज़ों की उस नीति का विरोध किया जिसमें किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी जाती थी और ऊँचे करों के बोझ तले दबाया जाता था। वे मानती थीं कि जब तक जनता को न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी शासक का शासन टिक नहीं सकता। उन्होंने धार्मिक आधार पर बंटवारे की साज़िशों का भी विरोध किया। वे हमेशा हिंदू और मुसलमान दोनों को एकजुट होकर अंग्रेज़ों से लड़ने की प्रेरणा देती थीं। कई मौकों पर उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों की सुरक्षा का आदेश दिया ताकि जनता में यह संदेश जाए कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं, बल्कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ़ है।

राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने चार्टर्ड अकाउटेंट्स एआई तकनीक बन रही डिजिटल क्रांति- मुख्यमंत्री

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउटेंट देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा हैं तथा उनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउटेंट्स से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता, विचारों एवं मेहनत से राज्य के विकास में अधिक से अधिक भागीदार बनें तथा देश-प्रदेश की प्रगति में योगदान दें, जिससे विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को गति मिले। शर्मा शुक्रवार को भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान, जयपुर शाखा द्वारा आयोजित 'एआई इनोवेशन समिट 2025' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा सीए राजस्थान से हैं। उन्होंने कहा कि सीए नई तकनीक आने पर, कोई नया नियम बनने पर अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आने पर सबसे पहले उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं और समाज को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आमजन को सीए पर बहुत विश्वास होता है, उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने एवं इस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है।

भारत एआई क्षेत्र में बना रहा तेजी से पहचान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर आ गया है तथा शीघ्र ही हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। शर्मा ने कहा कि एआई केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में आगे बढ़ रही है। भारत भी एआई क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। एआई भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया एआई मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारी सरकार नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी पर भी काम कर रही है।

राज्य में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, खनन, सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। साथ ही, राज्य में पेयजल एवं बिजली की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए गए। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। हम वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम— चिकित्सा मंत्री ने बच्चों को खिलाई एल्बेण्डाजॉल की दवा

-प्रदेश में 3.33 करोड़ बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जयपुर स्थित अपने राजकीय निवास पर बच्चों को एल्बेण्डाजोल की दवा खिलाई। उन्होंने बच्चों को दवा खिलाने के साथ ही उनके परिजनों को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित अंतराल पर यह दवा खिलाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और शारीरिक विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम देशभर में चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी इस कार्यक्रम का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के करीब 3 करोड़ 33 लाख बच्चों एवं किशोर—किशोरियों को एल्बेण्डाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन कर आंगनबाडी से लेकर विद्यालयों तक में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाओं की खुराक दिलवाई जा रही है। इससे बच्चों व किशोर-किशोरियों में कृमि संक्रमण के प्रसार में प्रभावी कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को दवा खाने से वंचित रहे बच्चों को 29 अगस्त को मॉप अप दिवस पर दवा खिलाई जा सकेगी।

निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि स्वस्थ्य बच्चे एवं स्वस्थ किशोर स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण घटक है। बच्चों व किशोर-किशोरियों में हीमोग्लोबिन की कमी (अनीमिया) का एक कारण कृमि संक्रमण भी है। कृमि अस्वछता और गन्दगी से फैलते हैं और संक्रमित मिट्टी के माध्यम से संचारित होते हैं। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्ति (डिवर्मिंग) करने से कृमि संक्रमण (पेट के कीडों की समस्या) के फैलाव को रोका जा सकता है।

परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि से मुक्त करने के उद्देश्य से 22 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दिन दवा लेने से वंचित रहे बच्चों हेतु 29 अगस्त को मॉप-अप दिवस का आयोजन किया जाएगा। बच्चों व किशोर-किशोरियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, मदरसों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों में एल्बेण्डाजॉल की गोलियाँ खिलाने की व्यवस्था की गई है।

खरीफ-2025 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा- सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता हो सुनिश्चित

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि खरीफ 2025 के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के सुविधापूर्वक एवं समय पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खरीफ 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश हुई है जो कि अच्छी पैदावार के संकेत हैं। राज्य सरकार किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं उर्वरक उपलब्ध करवा रही है।

किसानों एवं ग्रामीणों को करें जागरूक, ग्राम सभा का हो आयोजन-

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए एवं वर्मी कम्पोस्ट, ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सेमिनार आदि आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान संचालित किया जाए।

उर्वरक परिगमन पर लगे अंकुश-

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण किया जाए। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में राज्य से उर्वरक अन्य राज्यों में परिगमन को रोकने के लिये पर्याप्त संख्या में चैक पोस्ट स्थापित किए जाए। साथ ही, उन्होंने अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में चैक पोस्ट हो स्थापित,

बीट के आधार पर तय होगी शहर की सफाई व्यवस्था की जवाबदेही तय

-शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों से सख्ती से वसूल हो कैरिंग चार्ज

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, ऑनलाइन सर्विसेज़, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, संपर्क पोर्टल, बजट घोषणा सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार सहित जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने सभी जोन उपायुक्तों से सख्ती के साथ कहा कि प्रतिदिन फील्ड में जाए, मुख्य मार्गों सहित विभिन्न स्थानों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें। साथ ही निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों की बीट तय की जाए और उसी अनुसार उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। मुख्य मार्गों पर सफाई अभियान चलाकर सफाई की जाए तथा रोडसाइड कचरा पात्र भी लगवाये जाये। कचरा डिपो/जीवीपी पॉइंट (गारबेज वल्नरेबल पॉइंट) को शीघ्र सफाई कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही कैरिंग चार्ज भी वसूल किया जाए। नगर निगम ग्रेटर द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर करने के लिये प्रतिदिन नवाचार कर रहा है सीसीटीवी कैमरो की निगरानी सहित अब मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से जयपुरवासियों से शहर को स्वच्छ करने की अपील भी की जायेगी।

गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा अब तक समस्त जोनों एवं वार्डों में कुल 648 ओपन कचरा डिपो में से 558 ओपन कचरा डिपो समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही शेष 90 ओपन कचरा डिपो की समाप्ति भी टीमों द्वारा की जा रही है। जिससे उन्हें शीघ्र समाप्त कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों से 1 अप्रैल 2025 से अब तक लगभग 57 लाख 47 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया जा चुका है। इसके साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषी व्यक्तियों से 1 अप्रैल 2025 से अब तक लगभग 11 लाख से अधिक का कैरिंग चार्ज वसूल किया जा चुका है।

आयुक्त ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र आवेदकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने संपर्क पोर्टल पर 60 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, नगरीय विकास कर के संबंध में कैंप की प्रगति रिपोर्ट, आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए की जा रही फोगिंग संबंधी गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

नगर निगम ग्रेटर की अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

-1 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 5 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये चित्रकूट स्टेडियम के चारों तरफ व नारायण विस्तार कट मांग्यावास, एस.एम.एस. ट्रोमा सेन्टर, जी.टी. पुलिया के नीचे आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 1 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 5 केन्टर सामान जब्त किया गया।

उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये चित्रकूट स्टेडियम के चारों तरफ व नारायण विस्तार कट मांग्यावास, एस.एम.एस. ट्रोमा सेन्टर, जी.टी. पुलिया के नीचे आदि स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 5 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 1 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

कृषिवानिकी से किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु समझौता

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आरवीजेवीवीएस) एवं पिपलेश्वर ग्रीन फेड कृषक उत्पादक संगठन, तूँगा, बस्सी, जयपुर के मध्य आज कृषिवानिकी (एग्रोफोरेस्ट्री) को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करना, जलवायु सहनशीलता (क्लाइमेट रेसिलिएंस) को बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

आरवीजेवीवीएस की ओर से वी. केतन कुमार, उप वन संरक्षक (डीएफओ), जयपुर तथा पिपलेश्वर ग्रीन फेड कृषक उत्पादक संगठन की ओर से कमलेश कुमार सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए वी. केतन कुमार, डीएफओ जयपुर ने कहा कि "एग्रोफॉरेस्ट्री किसानों की आय बढ़ाने, समुदाय को मजबूत बनाने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक सहनशील पारिस्थितिकी तंत्र (क्लाइमेट रेसिलिएंट इकोसिस्टम) के निर्माण की दिशा में ठोस कदम है।" इस समझौते के अंतर्गत लगभग 300 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। उनके खेतों में फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त आय सृजित होगी तथा पर्यावरणीय संतुलन एवं जलवायु सहनशीलता सुनिश्चित होगी। कृषक उत्पादक संगठन किसानों को बागवानी संबंधी इनपुट एवं तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा तथा भविष्य में विपणन (मार्केट लिंकज) की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इस अवसर पर सुश्री सुलोचना चौधरी, सहायक वन संरक्षक, जयपुर, दिनेश कुमार राणा, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक (पीएमयू, आरएफबीडीपी), श्याम सिंह, प्रबंधक (एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज), हेमंत कुमार दीक्षित, आजीविका विशेषज्ञ तथा सुश्री बिन्नी मेहता, संचार विशेषज्ञ, आरएफबीडीपी परियोजना उपस्थित रहे।

शेष रही ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रूप से हो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रूप से नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलेवार एवं माहवार निर्धारित किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती राजपाल शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की अनुपालना में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप शेष रही लगभग 2600 ग्राम पंचायतों में दो वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। जिन जिलों में प्रगति लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) के स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि नवीन पैक्स के गठन की गति अभी से तेज रखी जाए, जिससे कार्य सुगमता से सम्पन्न हो और भविष्य में ज्यादा भार नहीं आए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है, ऐसे में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्यों में भी वृद्धि होगी। अधिकारी इन बढ़े हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से अपने आप को तैयार रखें। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों को आगामी दिनों में गठित की जाने वाली पैक्स की संख्या एवं अवधि का उल्लेख करते हुए कार्ययोजना तैयार कर प्रधान कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी जिन जिलों में नवीन पैक्स गठन के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

श्रीमती राजपाल ने कहा कि जो ग्राम पंचायतें अब शहरी क्षेत्र में आ चुकी हैं, उनकी पहचान कर उन्हें पृथक् किया जाए। उन्होंने नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति के बाद उसके रजिस्ट्रेशन एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिंक करने के बीच के अंतर को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही, एनसीडी पोर्टल पर भी डेटा निरन्तर अपडेट करने के निर्देश दिए।

संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) अनिल कुमार इस दौरान उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) एवं संबंधित जिलों के उप रजिस्ट्रार वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

विधायक यादव ने कहा — नगरपरिषद शाहपुरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया जाए

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलेक्टर जयपुर के सभागार में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय विधायक मनीष यादव ने नगरपरिषद शाहपुरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक का आयोजन शाहपुरा में स्वीकृत FSTP (फीकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) को लेकर किया गया।

विधायक यादव ने बताया कि इस योजना की स्वीकृति के समय शाहपुरा नगरपालिका थी, लेकिन अब इसे नगरपरिषद का दर्जा मिल चुका है, जिसमें कई ग्राम पंचायतों का विलय हो चुका है। वर्तमान में नगरपरिषद शाहपुरा की जनसंख्या लगभग 1.25 लाख तक पहुँच गई है। ऐसे में FSTP प्लांट इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। विधायक यादव ने कहा कि अब आवश्यकता सीवरेज लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की है। इसलिए FSTP प्रोजेक्ट को निरस्त कर इसके स्थान पर STP/सीवरेज लाइन का नया प्रपोजल तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। बैठक में अधीक्षण अभियंता RUIDP, PWD, PHED, JDA, अधिशासी अधिकारी नगरपरिषद शाहपुरा तथा टाउन प्लानर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

वली के चाहने वाले दीवाने रंज ओ गम से मुरझाया नही करते - गौरी

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद इम्तियाज़ खान गौरी ने कहा कि वली के चाहने वाले दीवाने रंज ओ गम से मुरझाया नही करते, यह शब्द गौरी ने जयपुर के शास्त्रीनगर में स्तिथ हिन्द मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत दाता अमानीशाह रहमतुल्लाह आलेह के उर्स में शिरकत करने के बाद में उपस्तीथ जायरिनों को संबोधित करते हुए कहे।

गौरी ने कहा कि वली एक विद्दत ट्रांसफार्मर की भांति होता है जो भी इनसे जुड़ता है तो वो रोशन हो जाता है और जो इनसे टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है।

गौरी ने कहा कि वली खुदा को राजी करने के लिए दुनिया से किनारा कर लेते है और अपनी पूरी जिंदगी को राहे खुदा में लगा देते है और खुद को फ़ना कर देते है खुदा इनकी सेवा से इतना खुश हो जाता है कि इनकी मजारों पर आने वाला कभी भी मायूस नही लौटता है।

गौरी ने शायराना अंदाज में कहा कि "हद तपे सौ औलिया, बेहद तपे सौ पीर, हद बेहद दोनो तपे, ताको नाम फकीर"!

इस अवसर पर दरगाह के खादिमो द्वारा इनकी दस्तारबंदी की गई । इस अवसर राजनीतिक सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों आदि उपस्तीथ थे।

विधायक की माँग पर क्षेत्र के पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। क्षेत्र के पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। क्षेत्रीय विधायक मनीष यादव के प्रयाशों से क्षेत्र के 6 पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा केंद्रों के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो गई है। इस स्वीकृति के अंतर्गत हाथनौदा, घासीपुरा, तेज़पुरा, बिलान्दरपुर, बिशनगढ़ और चारणवास में पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। विधायक मनीष यादव ने कहा कि इन भवनों के निर्माण से पशुपालकों को बेहतर पशु-चिकित्सा सुविधाएँ, आधुनिक उपचार व्यवस्था और समय पर सेवाएँ उपलब्ध होंगी। यह कदम पशुपालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। इस निर्णय पर क्षेत्रवासियों ने विधायक के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इसकी कुल राशि 1.70 लाख है।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए		**पानी के लिए**	
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय	2706624
वॉट्सएप नंबर	9414037085	फायर ब्रिगेड	2747400
कस्टमर केयर	2203000	**मेडिकल इमरजेंसी के लिए**	
आईवीआरएस	1912	एंबुलेंस	102/ 108
कचरा गाड़ी के लिए		एसएमएस इमरजेंसी	2518333
ग्रेटर	2747400	महिला चिकित्सालय	22610616
सीवरेज लीकेज	2607500	जनाना हॉस्पिटल	22378721
हेरिटेज	2607500	SDMH	22574189
टोल फ्री नंबर	14420	SMS ब्लड बैंक	22518222
पुलिस की मदद के लिए		कल्याण ब्लड बैंक	22721771
साइबर क्राइम	1930/2360094	**घायल पशुओं के लिए**	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	नगर निगम	2747400
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	बर्ड बाइक	9887345580
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	हेल्प इन सफरिंग	8107299711
महिला हेल्पलाइन	1090	जनमंच ट्रस्ट	7230055800
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	पशु चिकित्सालय	2747400

सवाई माधोपुर में फिर बाढ़ का कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त

-रेलवे जंक्शन जलमग्न कई ट्रेने प्रभावित, खंडार की उगाल पुलिया फिर टूटी

- सूरवाल डेम में नाव पलटी एक लापता,कुशाली दर्रा के पास नाले में कार सवार तीन लोग बहे मौत

शादाब अली

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जिले में एक बार फिर तबाही मचा दी है। रातभर चली बारिश के चलते कई मोहल्लों में पानी घरों तक घुस गया और आमजन का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। पिछले महीने 30 जुलाई को हुई भारी बरसात से लोग अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जल त्रासदी जनहानि और भारी नुकसान का कारण बन सकती है। जिला प्रशासन 23 दिन पहले आई बाढ़ के बाद भी ठोस इंतज़ाम करने में नाकाम रहा है। आमजन का आरोप है कि यदि प्रशासन मुस्तैदी से काम करता तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। गरीब तबका इस अतिवृष्टि की मार को सहन नहीं कर पा रहा है। पिछली बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा भी पूरी तरह नहीं मिला और इससे पहले ही एक और संकट ने उन्हें घेर लिया। शहर के अंसारी मोहल्ला, कुम्हार मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, हम्माल मोहल्ला, कागज़ी मोहल्ला और भेरू दरवाज़े के आसपास के बाज़ार सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। देर रात से सुबह 5 बजे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके बाद कुछ समय रुकी, किंतु दोबारा बारिश का दौर जारी है।

स्थानीय विधायक आपदा प्रबंधन मंत्री भी

पूर्व विधायक दानिश अबरार ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को संदेश जारी करते हुए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है और कहा कि यह समझना आवश्यक है कि आखिरकार लोगों के घरों में पानी क्यों घुस रहा है। उन्होंने स्थानीय मंत्री एवं सांसद से विशेष अपील की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। दानिश अबरार ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी कारणों के चलते वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी संवेदनाएँ और सहयोग पीड़ितों के साथ हैं।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में गौड़ विप्र वरिष्ठतम सम्मान समारोह का आयोजन

रतनगढ़ (रॉयल पत्रिका) । गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में गौड़ विप्र वरिष्ठतम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । जिसमें दस वरिष्ठ सदस्यों पांच पुरुष सीताराम धर्ड़, परमेश्वर लाल मिश्र, मांगीलाल ताम्रायत, ओंकार मल सांखोलिया, सागर मल आत्रेय गोगासर, एवं पांच महिला मोहिनी देवी पत्नी गौरीदत्त बबेरवाल, नर्बदा शर्मा पत्नी भगवत शरण शर्मा, अनुसुइया देवी मिश्र पत्नी परमेश्वर लाल, कृष्णा देवी पत्नी शिवलाल घाघसान, ज्याना देवी पत्नी बंशीधर महर्षि का शॉल, दुपट्टा श्रीफल, अभिनन्दन पत्र भेंट कर सम्मान किया किया गया । समिति अध्यक्ष जयप्रकाश ताम्रायत ने बताया

कि कार्यक्रम स्वर्गीय गंगा देवी पत्नी वैद्य गुणज्ञप्रसाद सिंवाल के सुपुत्र मुरारीलाल सिंवाल एवं समस्त सिंवाल परिवार सांगासर के सौजन्य से आयोजित किया गया इस मौके पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभव सांझा किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष जयप्रकाश ताम्रायत, कार्यक्रम संयोजक विष्णुदत्त धर्ड़, घनश्याम चन्द्र सिंवाल मुंबई, सुरेन्द्र हारित, आनंदी लाल आत्रेय, पवन पचलंगिया, हरि प्रसाद बुटालिया, मनोहर लाल चौमाल, वासुदेव चाकलान,अरविंद घाघसान, अरविंद महर्षि, मनोज चौमाल, जगमोहन हारित रामोतार शर्मा, अनिल आत्रेय, संरक्षक संतोष बाबू इंदौरिया, गौतम महर्षि, युवक संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा, महिला मंडल अध्यक्ष यशोदा शर्मा, पुष्पा शर्मा,कुसुम सांखोलिया, बबीता धर्ड़, बेबी पंचलंगिया सहित समाज के गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

बिनासर में जल समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग का किया घेराव

चूरू (रॉयल पत्रिका)। गाँव बीनासर में आरही पेयजल व पानी की परेशानी को लेकर गाँव वासियों ने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता पिएचईडी कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज करवाया। और कहा कि अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान न होने पर गाँव वासियो के साथ उग्र प्रदर्शन एव जलदाय विभाग का घेराव किया जाएगा। ग्राम वासियों के साथ काफी संख्याओं में महिलाओं ने सर पर खाली मटके लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का चुरु बाईपास पर कांग्रेस जनों ने किया स्वागत

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के नजदीक चूरू बाईपास रतननगर हाइवे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का चूरू जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ के नेतृत्व में स्वागत किया। पीसीसी सचिव रियाज़त खान, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर देहात अध्यक्ष किशोर धांधू, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान, रतननगर अध्यक्ष असलम खान, जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामनारायण व्यास, उम्मेद सिंह राठौड़,विक्रम पाल, आदुराम न्यौल, नारायण बालान, संजय भाटी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोयल खान डीके, पार्षद इस्माइल भाटी, सिराज जोया, आरिफ़ रिसालदार,पार्षद सब्बीर अली, जगनराम, मजीद मुंशी, डूंगरसिंह, सुरेंद्र कुमार ढड,श्रवण बसेर, इमरान राणासर, रमजान कुरैशी, नानूराम राठी, साहिल खान, प्रताप पुनिया, आदि ने किया। इस अवसर पर गोविंद डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओ को निकाय और पंचायतों के चुनाव की तैयारी के सम्बन्ध मे सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए कहा इस सरकार पर आपको पेनी नजर रखनी होगी। यह लोकतंत्र और संविधान में कम विश्वास रखते है। आपको एकजुटता के साथ चुनाव में उतरना है और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है।

बाबा रामदेव महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह व विशाल भंडारा 25 को

चौमूं। शहर के जयसिंहपुरा (गुवारड़ी) ग्राम में स्थित बाबा रामदेव जी महाराज मंदिर प्रांगण में भक्तजनों एवं सभी ग्रामवासियों के जनसहयोग से 25 अगस्त को लोक देवता श्री बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह व विशाल भंडारा का आयोजन होगा। इससे पूर्व 24 अगस्त को सुबह 9:15 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक मंगल कलश यात्रा एवं रामायण पाठ का आयोजन होगा। 25 अगस्त को सूर्योदय से हवन, सुबह 9:18 से 10:53 बजे तक महाभिषेक, सुबह 11:15 बजे से 12:15 बजे तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके पश्चात सांय 3:15 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन होगा।

अमीन पठान को राजस्थान खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय से जिला फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष शकील दुर्रानी व सचिव सुरेंद्र सिंह मेड़तिया ने जयपुर मै आमीन पठान से मिलकर उनको खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनके आवास पर मिलकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ मै हमीद खान रिसालदार, डॉक्टर वसीम अंसारी, पंकज सोनी, उपस्थित रहे! पुष्प भेंट कर खेलों पर चर्चा की।

चौमूं शहर स्थित हजरत दौलत शाह बाबा रहमतुल्ला आले के 215 वे उर्स का समापन

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। चौमूं शहर में हजरत दौलत शाह बाबा रहमतुल्लाह आले का 215 उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या मे जायरानों का लगातार तीनों दिन हुजूम देखने को मिला 19 अगस्त से चार दिवसीय उर्स का आयोजन चौमूं शहर में चल रहा था। 19 अगस्त को दरगाह पर रोशनी का आयोजन हुआ 20 अगस्त को कुरान खानी व 21 अगस्त को, सुबह लंगर तबर्रुक वितरित किया गया, बाद नमाज ईशा के महफिले शमा का आयोजन हुआ जयपुर के मशहूर कव्वाल पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक हजरतदौलत शाह बाबा की शान में कलाम पेश किए गए, बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पर मौजूद रहे और बाबा की शान में कलाम सुन कर झूमने लग गए बूढ़े बच्चे महिलाएं तरह तरह से सजी खिलौनों की दुकानों पर खरीदारी कर रही थी शुक्रवार को बाद नमाज अशर के कुल की रस्म अदा हुई ये कमेटी के लोग मौजूद रहे, ईरशाद अली सचिव, अब्बास खान, इकबाल खान, मीनाज खान सलीम खान, नौशाद खान, रमजान नीलगर, याकूब बाबा, अब्दुर रहमान, लियाकत बाबा महमूद खान, शरीफ खान, लतीफ खान, मुमताज खान, समसीर खान,और भी कई शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासन मय जाप्ते के मौजूद रहा sho प्रदीप शर्मा खुद मौके पर मौजूद रह कर व्यवस्था देख रहे थे।

वार्ड संख्या 58 की जन समस्याओं को लेकर नगर परिषद आयुक्त को दिया ज्ञापन

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर वार्ड संख्या 58 के निवासियों ने नगर परिषद आयुक्त को जावेद खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि वार्ड में सड़कों, नाली, जल भराव, बिजली, पानी,की समस्या और गंदगी को लेकर आज हम वार्ड वासी नगर परिषद आयुक्त से मिले और ज्ञापन दिया है हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्य करवाए जाएंगे। हमारे वार्ड में चेजारों की धर्मशाला से लेकर हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी शिक्षाविद् के घर तक टूटी हुई सड़क और अनवर चेंजरा घर से ख़ुशी अंसारी के घर तक टूटी हुई सड़क इन सड़को का 15 सालो से कोई भी रिपेयर या निर्माण नहीं हुआ है और नहीं सिवरेज लाइन गिरी है यह गुगामेड़ी पुरानी कब्रिस्तान शमसान घाट का

मुख्य रास्ता है। इस रास्ते से सर्व समाज का जनाजा व अर्थी जाती हैं यह रास्ता टूटा फूटा होने से बडे बूढ़े बुजुर्ग गिरने के कारण चोटिल हों जाते है और बरसाती पानी जमा हो जाता है और बड़ी स्ट्रीट लाइट की भी काफ़ी आवश्कता है कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया अगर अब किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई तो अब सम्पूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद चूरू की होंगी और जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में आसिफ अंसारी, इरफान ,सोयल छिंपा, आदिल लीलगर, आसिक खान, सोयल, शाहरुख, अरमान मोयल, समीर मोयल, अनीस मोयल, सेफ अली खान, साहिद खान, आदिल चायल, वसिम चेजारा, आसिन छिपा, दोलिया, तालिम खान, समीर, अरमान, साजीद मोयल आदि उपस्तिथ रहे।

राष्ट्रीय कृमी मुक्ति दिवस पर स्कूल में बच्चों को कर्मी नाशक एल्बेड़ाजोल गोलिया खिलाई गई

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर इन्दिरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को 22 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि नाशक एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई गई इस मौके पर विधालय संचालक अख्तर खान रूकनखानी ने कहा कि कुपोषण में खून की कमी का मुख्य कारण पेट में कृषि होना है देश का बचपन स्वस्थ होगा तभी युवा सक्षम सशक्त व स्वस्थ होंगे संस्थान सचिव हाजी युसूफ खान रूकनखानी ने कृमि रोग से बचाव के तरीकों की जानकारी दी प्रधानाध्यापिका सबीना बानो ने विचार व्यक्त किए इस मौके पर अनुदेशिका अल्लादेई अनुदेशक असलम खान अनुदेशक जान मोहम्मद एवं समाजसेवी यूनुस खान रूकनखानी आदि मौजूद थे।

लोहरवाड़ा में किया सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। बलाई विकास समिति जयपुर एवं लोहरवाड़ा ग्राम इकाई के संयुक्त तत्वावधान में 24 अगस्त को लोहरवाड़ा तंवर कृषि फार्म हाउस में होने वाले पौधारोपण एवं वर्ष 2024-25 में सेवानिवृत कार्मिकों का सम्मान समारोह को लेकर लोहरवाड़ा समाजबंधुओं ने पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष एडवोकेट बद्रीनारायण परिहार, उपाध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम बुनकर, राजपालसिंह नारनोलिया, कोषाध्यक्ष घनश्याम कांदेल, सचिन प्रहलाद राय जाटावत, ओमप्रकाश गढ़वाल, लोहरवाड़ा ग्राम इकाई अध्यक्ष गोपाल लाल तंवर, उपाध्यक्ष मदनलाल तंवर, कोषाध्यक्ष धीरज कुमार बुनकर, सरपंच मनोहर सरावता, प्रभुदयाल सरावता, मोहनलाल, जितेंद्र सरावता, कैलाश तंवर, अमरनाथ सरावता, लक्ष्मण सरावता, प्रभु दयाल तंवर, बाबूलाल तंवर, नितिन तंवर आदि समाजबंधु मौजूद रहे।

डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय संविधान के उदघोष के बीच नईमुद्दीन गुड्डू ने किया लाडपुरा प्रधान पद ग्रहण

कोटा (रॉयल पत्रिका)। लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड् ने अपने समर्थकों के साथ बरसती मूसलाधार बारिश में न्यायालय परिसर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय संविधान के उदघोष के बीच लाडपुरा समन्वयक अनिल आनन्द, ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन आईना महक, पूर्व प्रधान राजेन्द्र मेघवाल, सरपंच मोइजुद्दीन गुड् सहित सैकड़ों समर्थकों के बीच प्रधान पद का पदभार ग्रहण किया।

प्राधिकरण सचिव भाटी ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण

पाली (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली विक्रम सिंह भाटी ने गुरूवार को जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 96 बन्दी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले।

इस दौरान सचिव भाटी द्वारा बन्दीगण से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त कोई भी बन्दी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हो अथवा विधिक सहायता के अभाव में बिना अधिवक्ता के कारागृह में निरूद्ध ना रहे, इसके लिए सचिव भाटी द्वारा कारागृह में बन्दीगण को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए ऐसे बन्दी जिनकी जमानत होने के उपरांत भी कारागृह में निरूद्ध हो इस संबंध में भी जानकारी ली गई तथा बंदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही इस बात की भी जानकारी ली गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जिला कारागृह में निरूद्ध न रहे। सभी बन्दी की ओपीडी के समय में स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा इमरजेन्सी होने पर बन्दीगण को राजकीय बांगड़ अस्पताल रेफर किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कारापाल जिला कारागृह जोराराम, जेल विजिटिंग लॉयर अल्ताफ हुसैन, विनीता प्रजापत आदि उपस्थित रहे।

कामासर राउमावि में भामाशाह अमरी देवी ने बनवाया प्रवेश द्वार

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिले के सरदारशहर तहसील के कामासर राउमावि में स्व. रामचन्द्र मेहरा की 15 वीं पुण्य तिथि पर उनकी धर्मपत्नी अमरी देवी एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पहल करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी, ग्रामवासी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में श्रद्धा व सम्मान के साथ द्वार का उद्घाटन किया गया।ग्रामीणों ने इस पहल पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि स्व. रामचंद्र मेहरा का हमेशा से गांव के शैक्षणिक उन्नयन की सोच रही है। उनकी इसी सोच को साकार करते हुए उनके परिवार द्वारा समाज सेवा का यह प्रयास प्रेरणादायी पहल है। यह योगदान आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के प्रति समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित करेगा। इस मौके पर स्व.रामचंद्र मेहरा की धर्मपत्नी अमरी देवी, सुपुत्र लालचंद, कन्हैयालाल, शिशराम, पुत्रवधू पिंकी, चंचल, सुपुत्री संतोष, मंजू, सोपुत्र रवि प्रकाश, गणेशराम, भंवर लाल, मांगीलाल, श्रवण कुमार, विकास कुमार सहित मेहरा परिवार सदस्य तथा गोपीराम जागिड़ , सहीराम नायक, सत्यवीर कस्वां, गिरधारी लाल शर्मा, खिंवाराम जाट आदि गणमान्य नागरिक, कार्यवाहक संस्था प्रधान वेद देव सिंह सारण, बलराम सहित अध्यापकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

जिला कलेक्टर ने बच्चों को दवा खिलाकर की कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के खुंजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जहां जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों, सरकारी व निजी विद्यालयों, मदरसों और तकनीकी संस्थानों में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने कहा कि कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर प्रतिकूल असर डालता है। पेट में कीड़े पड़ने से बच्चों का विकास रुक जाता है, जिसे समय-समय पर कृमि नाशक दवा खिलाकर रोका जा सकता है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को एल्बेंडाजॉल की गोली अवश्य खिलाएं।

एक से 19 वर्ष तक के बच्चों को मिली दवा

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में शुक्रवार को 6 से 19 साल तक के बच्चों को विद्यालयों और एक से पांच साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में कृमि नाशक दवा दी गई है। एक से दो साल तक के बच्चों को आधी गोली चूर कर पानी के साथ, दो से तीन साल के बच्चों को पूरी गोली चूर कर पानी के साथ, तीन से 19 साल तक के बच्चों व किशोरों को पूरी गोली चबा कर पानी के साथ दी गई है। डॉ. शर्मा ने कहा कि जो बच्चे शुक्रवार को दवा नहीं ले पाए, उन्हें 29 अगस्त को मॉपअप राउंड में दवा दी जाएगी। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. अखिलेश शर्मा ने बच्चों को हाथ धोने की विधि 'सुमन-केÓ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाना खाने से पहले हाथ धोना बेहद जरूरी है, क्योंकि गंदे हाथों से भोजन करने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जो पोषण क्षमता को घटाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं।

रोजगार सहायता शिविर में 534 का हुआ प्रारंभिक चयन

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 750 आशार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 534 आशार्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू ने शिविर में उपस्थित आशार्थियों को प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायता शिविर में पुखराज हैल्थ केयर प्रा.लि., प्रथम ऐज्यूकेशन फाउण्डेशन पिलानी, राक्षा सेक्योरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेईटीआई, सीआईआई एमसीसी, एसबीआई जीवन बीमा, चूरू ग्लेयर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया इन्सोरेंस, स्वतंत्र माइक्रो फाईनेन्स, जेब्रस इंडिया ओपीसी प्रा. लि., प्राइमरोज एण्ड सिक्योरिटी प्रा.लि., इत्यादि कम्पनियों ने साक्षात्कार के माध्यम से बेरोजगार आशार्थियों का प्रारम्भिक चयन किया। इसी के साथ जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार व ऋण योजनाओं सम्बंधी जानकारी दी गई। शिविर में शामिल नियोजकों ने विभिन्न पदों की रिक्तियों के बारे में जानकारी दी। संचालन वरिष्ठ सहायक संदीप न्यौल ने किया। इस दौरान कनिष्ठ रोजगार अधिकारी सुशीला कताला, वरिष्ठ सहायक संजय गोस्वामी व सूचना सहायक मुकेश कुमार ने सहयोग किया।

ग्राम पंचायत सुराता में सीईओ राठौड़ ने चौपाल में सुनी परिवेदनाएं

- ग्रामीणों की परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में आमजन की समस्याओं को निस्तारित कर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने गुरुवार को ग्राम पंचायत सुराता में रात्रि चौपाल की और ग्राम वासियों की परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

पंचायत समिति झोथरी की ग्राम पंचायत सुराता में गुरुवार को आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने विद्त पोल बदलने, सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति जाने उचित मूल्य दुकान के जर्जर भवन के मरम्मत करवाने,विद्यालय के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति, वन विभाग की भूमि पर मिनी बांध बनवाने सहित अन्य परिवेदनाएं लेकर बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित हुए तथा अपनी परिवेदनाओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ को के समक्ष प्रस्तुत की । सीईओ राठौड़ ने एक-एक परिवादी की परिवेदना को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नियमानुसार समाधान के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान चौपाल में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पर रात्रि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने रात्रि चौपाल उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं अन्य को भी जागरूक करें। उन्होंने रात्रि चौपाल के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि चौपाल में जितनी भी परिवेदनाएं आई है उनको ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर उनको शीघ्र ही निस्तारित करवाई जाएगी ।

यह आई परिवेदनाएं-

चौपाल में आई परिवेदनाएं हेड पंप लगवाने, माहुरिया फला ग्राम पंचायत सूराता में नवीन प्राथमिक विद्यालय मां बाड़ी केंद्र खोलने, पगडंडी रास्ते पर सड़क बनवाने, उचित मूल्य दुकान सूराता सेकंड का भवन जर्जर अवस्था में मरम्मत करवाने, साझा फला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद का अनुमोदन, विद्त पोल बदलने, सीसी सड़क स्वीकृत करवाने, जर्जर क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन को नवीन भवन स्वीकृत करवाने, मिनीबांध का निर्माण, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति, खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाने, ग्राम पंचायत माल को सीमांकन करवाने, आदि परिवेदनाओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण कर राहत प्रदान करने की निर्देश दिए।

प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का किया अभिनंदन-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुराता में अध्यनरत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के कला एवं विज्ञान संकाय के छात्र-छात्राओं को माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया।

जनसुनवाई में किया आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान सरकार की जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर सुभाष कुमार ने आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप पीड़ित को राहत व संतुष्टि दिलवाना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त 171 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। जनसुनवाई के दौरान लालगढ जाटान के वार्ड नम्बर 1 में पेयजल समस्या में कार्यवाही करने हेतु पीएचईडी अधिकारी को निर्देशित किया। वृद्धा सुन्दर देवी के भरण पोषण प्रकरण में एडीएम अनूपगढ़ को जांच कर परिवादी को जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के निर्देश दिये। 7 एफ में अतिक्रमण को हटाने के लिये जिला परिषद एसीईओ को निर्देशित किया गया। लाधुवाली पीएचसी प्रकरण में चिकित्सक को समय पर आने, 3 वाई में पीएम आवास योजना में प्राप्त प्रकरण में पट्टा बनवाने के लिये जिला परिषद, लालगढ़ जाटान में सिंचाई विभाग की जमीन पर खेती करने व पेड़ काटने के संबंध में प्राप्त प्रकरण में एसडीएम सादुलशहर को जांच कर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया। राशनकार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रथम किश्त के प्रकरण में जिला परिषद, पति की मृत्यु से संबंधित क्लेम प्रकरण में नियमानुसार लाभ दिलवाने के लिये उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया। 2 पी अनूपगढ में रास्ते की जमीन में खाला प्रकरण, साधुवाली में पीएचईडी विभाग द्वारा पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद टूटी हुई सड़कों की पुनः मरम्मत करवाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। करड़ावाली में पानी की बारी काटने हेतु प्राप्त प्रकरण में एसई आईजीएनपी विजयनगर को और 6 ई छोटी में बंद रास्ता की जांच के लिये एसीईओ को निर्देश दिये गये।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षकों ने सीखा व्यावहारिक अभ्यास से दक्षता वृद्धि एनसीईआरटी कार्यशाला का चौथा दिन

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जारी एनसीईआरटी कार्यशाला के तहत गुरूवार को शिक्षकों ने व्यावहारिक अभ्यास से दक्षता वृद्धि की तकनीकों की सीख ली। उन्होंने संतुलित प्रश्न-पत्र निर्माण की बारीकियों के बारे में भी जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित कार्यशाला के चौथे दिन संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण की बारीकियां तथा व्यावहारिक अभ्यास द्वारा शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। प्रथम सत्र में परख के विशेषज्ञों ने संतुलित प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इसमें प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों का चयन, संयोजन, अंक निर्धारण योजना तथा प्रश्न पत्र के विश्लेषण एवं मॉडरेशन की प्रक्रिया सम्मिलित रही। द्वितीय सत्र में सहभागियों ने हाथों-हाथ गतिविधि के माध्यम से आकलन डिज़ाइन निर्माण की व्यावहारिक समझ विकसित की। विशेषज्ञों ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न स्तरों के प्रश्नों को संतुलित ढंग से सम्मिलित किया जाए ताकि मूल्यांकन में सभी अधिगम लक्ष्यों को समाहित कर सके। तीसरे सत्र में शिक्षकों को संतुलित प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पर गहन अभ्यास कराया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने लिए अधिकारियों की बैठक

-खाद्य सुरक्षा सूची से 54 हजार से अधिक लोगों ने हटाया नाम, 1 लाख 23 हजार नए लाभार्थी योजना से जुड़े

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को जिला परिषद के ग्रामीण विकास अधिकरण सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मंत्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए गिव अप अभियान महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 54,272 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटाकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनकी पहल से जरूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना का सीधा लाभ सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की सफलता का परिणाम है कि जिले में अब तक 1,23,000 नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और पारदर्शिता लाने में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए लाभार्थियों को समय पर राशन कार्ड जारी कर योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी सहित सभी प्रवर्तन अधिकारियों से सेक्टर की नाम जोड़ने खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के संबंध में की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली । बैठक में विधायक चित्तौड़गढ़ चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, जिला कलक्टर आलोक रंजन, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, रतन गाडरी, जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे और अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया। मंत्री गोदारा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि "कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे।" उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग से भी अपील की कि वे स्वेच्छा से गिव अप अभियान से जुड़कर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं।

जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल प्रकरणों के निस्तारण में बेहतर कार्य कर डूंगरपुर शीर्ष पांच में

-जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलक्टर सिंह ने सुनी परिवेदनाएं, निस्तारण के लिए निर्देश

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक एवं जनसुनवाई में प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई। इसमें डूंगरपुर जिला ने जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण में विभिन्न मानकों में बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में सम्मिलित हुआ है। डूंगरपुर जिला ने इन प्रकरणों में एवरेज डिस्पोजल टाइम तथा सेटिस्फेक्शन रेट में उत्कृष्ट कार्य किया है। गुरुवार को समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव पंत ने जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल प्रकरणों के निस्तारण में पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से कार्य करने एवं गुड गवर्नेंस की मंशा को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रकरणों को तेजी से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए सराहना करते हुए कहा कि बेहतर कार्य करने वाले सभी जिले बधाई के पात्र हैं। डूंगरपुर डीओआईटी सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में मुख्य रूप से वनाधिकार पट्टे, नाला मरम्मत, अवैध निर्माण रोकने, म्यूटेशन खुलवाने, भूमि अवाप्ति में मुआवजा दिलवाने, आधार कार्ड बनवाने आदि परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिला कलक्टर सिंह ने प्रत्येक परिवादी से परिवेदना को तसल्ली से सुना तथा संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जहां आवश्यक है वहां जांच करने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अन्य प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए निस्तारण के निर्देश प्रदान किये। जनसुनवाई के दौरान एडीएम दिनेश चंद्र धाकड़, एसीईओ अनिल पहाड़िया सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहें।

जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

-जिला कलक्टर ने 85 प्रकरणों की की सुनवाई, अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय जनसुनवाई की मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा मॉनिटरिंग की गई। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रि चौपाल, स्थलीय निरीक्षण एवं ई-फाइल निस्तारण की नियमित समीक्षा कर सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने जनता से अच्छे आचरण, महिला कार्मिकों से सम्मानजनक व्यवहार एवं स्वयं के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधि करने को कहा। वित्तीय समावेशन शिविरों में अधिक लोगों को जोड़ने, फसल बीमा योजना में संतृप्ति स्तर तक प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों का बीमा कराने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने एवं फॉर्मर रजिस्ट्री शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क एवं सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, छह माह से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता से निस्तारण तथा शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता एवं संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलक्टर लोक बन्धु ने 85 प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में सड़कों की मरम्मत, खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने, पाइपलाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत कराने, बांदरसिंदरी बस स्टैंड के समीप रोड़ की चौड़ाई बढ़ाने, राशन की केवाईसी, राशन में परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करने, पेयजल की पाइपलाइन, चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, ग्राम लीडी में पेयजल आपूर्ति समय पर कराने, अवैध पट्टा निरस्त कराने, किशनगढ़ के न्यू हाउसिंग बोर्ड एक्सटेंशन क्षेत्र में नालियों की सफाई कराने, पत्थरगढ़ी कराने, रास्ता खुलवाने, पेंशन, जनआधार अपडेट कराने, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने, नाले एवं नालियों की सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई की राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत माह के प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। जून माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जनसुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 85 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किया गया। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीपी ग्राम एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और 6 माह से अधिक लंबित मामले शीघ्र निपटाया जाए।

वित्तीय समावेशन योजनाओं के संबंधित अभियान के शिविर होंगे आयोजित

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जिले में वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं से संबंधित अभियान आगामी 30 सितम्बर तक संचालित होंगे। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर जन-धन खातों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लाभांवित किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक संजय कुमार सिंह ने बताया कि शिविरों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के पुराने खातों की केवाईसी करने के साथ ही नए जन-धन खाते हाल ही में व्यस्क हुए व्यक्तियों के खोले जाएंगे। शुक्रवार, 22 अगस्त को अजमेर ग्रामीण की रसूलपुरा, अरांई की मनोहरपुरा, किशनगढ़ की रूपनगढ़, केकड़ी की खवास में शिविर आयोजित होंगे। इसी प्रकार सोमवार, 25 अगस्त को किशनगढ़ की बरना, पीसांगन की गोविन्दगढ़, श्रीनगर की लोहरवाड़ा, सरवाड़ की हिंगोनिया में शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 26 अगस्त को अरांई की सांडोलिया, किशनगढ़ की भट्टून, सावर की गोरधा, पीसांगन की नागेलाव, 27 अगस्त को किशनगढ़ की दिंदवाडा, पीसांगन की जेठाना, भिनाय की एकलसिंगा, 28 अगस्त को अरांई की भगवंतपुरा, अजमेर ग्रामीण की दौराई, किशनगढ़ की सुरसुरा, केकड़ी की कोहड़ा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जन सुरक्षा शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। ग्राम पंचायत 9 एफए माजीवाला, करड़वाली व बिलोचिया में जिला अग्रणी बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा जन सुरक्षा एवं वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संयुक्त निदेशक (योजना) सुभाष चंद्र गुप्ता, उप निदेशक (सांख्यिकी) सुशील शर्मा, एलडीएएम मुकेश जांगड़ा ने विशेष रूप से भाग लिया। स्थानीय बीएसओ, वीडीओ व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रमों में आरोह फाउंडेशन के प्रतिनिधियों, एफएलसी कृष्ण लाल सैनी और उपस्थित बैंक कर्मियों ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी। साइबर क्राइम से बचाव एवं सुरक्षा उपायों पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया और खाता सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति से पैसे अपने खाते में जमा न करवाना और व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी साझा न करना की जानकारी दी गई।

डीजे सुथार ने तपोवन महिला आश्रय स्थल में की विजिट

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा मासिक एक्शन प्लान के अनुसार गुरूवार को तपोपन महिला आश्रय स्थल 3 के श्रीगंगानगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर वृद्ध व शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। एडीजे सुथार ने महिला आश्रय स्थल में सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर मानसिक रूप से मंदबुद्धि महिलायें भी निवासरत होना पाई गई। महिलाओं के खाने व पीने योग्य का पानी का जायजा लिया। आश्रयत स्थल में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था पाई गई। इस दौरान मौके पर सुलोचना चौधरी, प्रबंधक, भादर राम, लिपिक सहित स्टाफ उपस्थित रहा।

वित्तीय साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को दी उपयोगी जानकारी

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। ग्राम पंचायत 9 एफ, माझीवाला, ब्लॉक श्रीकरणपुर में सीएफएल पदमपुर की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरोह फाउंडेशन सीएफएल पदमपुर और पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। इस अवसर पर ग्रामीणों को वित्तीय जानकारी प्रदान की गई और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। डिजिटल लेन-देन, जमा-निकासी प्रक्रियाएं एवं बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी गई। साइबर क्राइम से बचाव एवं सुरक्षा उपायों पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। खाता सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिनमें किसी अपरिचित व्यक्ति से पैसे अपने खाते में जमा न करवाना और व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी साझा न करना।

शिविर में एएफसी नरेश बिश्नोई (आरोह फाउंडेशन), ग्राम पंचायत सरपंच जेठा लाल, वीडीओ अनिल कुमार, पंजाब एंड सिंध बैंक श्रीकरणपुर से शाखा प्रबंधक अभिषेक सैनी, देवीलाल, नवनीत सिंह उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त अग्रणी बैंक श्रीगंगानगर से एलडीएम मुकेश जांघड़ा, एफएलसी कृष्ण लाल सैनी, सांख्यिकी विभाग से संयुक्त निदेशक सुभाष चंद्र गुप्ता, उप निदेशक सुशील कुमार, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हेमलता एवं प्रगति प्रसार अधिकारी डॉ. राकेश कुमार ने भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता से जोड़ना और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना रहा।

विद्यार्थियों को 'मुझे गर्व है, मैं नशा मुक्त हूँ' सुरक्षा कवच पॉकेट बैज वितरित

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर डॉ. मंजू एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के नेतृत्व में जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत भारत-पाक सीमावर्ती पाँच विद्यालयों कोठा, पक्की, हिन्दमलकोट, ओड़की और दुलापुरकेरी के विद्यार्थियों को 'मुझे गर्व है, मैं नशा मुक्त हूँ' सुरक्षा कवच पॉकेट बैज वितरित किए गए। विद्यालयों के प्राचार्य ने अपने-अपने स्टाफ के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विक्रम ज्याणी ने आज से हर विद्यार्थी यह बैज पहनकर समाज को संदेश देंगे कि नशा करना शर्म, नशा मुक्त रहना ही सबसे बड़ा गर्व है। यह बैज केवल कपड़े पर लगा चिन्ह नहीं, बल्कि नशे से दूर रहने का आत्मसम्मान है। विद्यार्थी हर दिन यह संदेश गर्व से समाज तक पहुँचाएँगे। कार्यक्रम में सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलवाई गई।

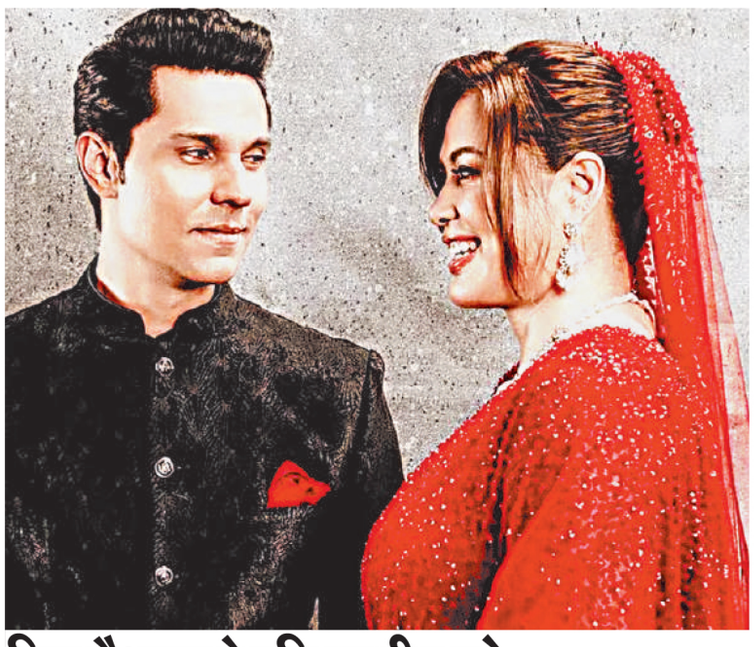

लिन लैशराम ने पति रणदीप को

खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

अभिनेत्री लिन लैशराम ने पति और अभिनेता रणदीप हुड्डा को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिन ने छोटा मगर प्यारा कैप्शन भी दिया। दमदार अभिनय शैली के लिए मशहूर रणदीप ने मॉनसून वेडिंग, साहेब बीवी और गैंगस्टर, हाईवे, सरबजीत और स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसी फिल्मों से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री लिन लैशराम ने बेहद खास और दिल छू लेने वाला अंदाज अपनाया। लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें रणदीप केक काटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ लिन ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। रणदीप और लिन की जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक है। दोनों ने 29 नवंबर 2023 को इम्फाल, मणिपुर में पारंपरिक मेइतेई रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी। इस शादी में रणदीप ने मणिपुरी संस्कृति को अपनाते हुए पारंपरिक पोशाक पहनी थी, जबकि लिन ने पोटलोई पहनकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। रणदीप के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह न केवल अपनी शानदार एक्टिंग स्किल बल्कि किरदारों के लिए किए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी जाने जाते हैं। रणदीप के इस पैशन ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दी है। विदेश में पढ़ाई करने के बाद रणदीप ने मॉडलिंग और थिएटर शुरू किया। साल 2001 में उन्हें बड़ा मौका मिला। मीरा नायर की 'मॉनसून वेडिंग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' (2010) ने उन्हें स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में काम किया। नसीरुद्दीन शाह के मोटली थिएटर ग्रुप से रंगमंच पर उतरे। रणदीप स्वतंत्र वीर सावरकर, दो लफ्जों की कहानी, सरबजीत, जाट, हाईवे जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं।

'कंचना 4' में नोरा फतेही की एंट्री

बोलीं- 'तमिल डेब्यू के लिए परफेक्ट फिल्म'

एक्ट्रेस नोरा फतेही लोकप्रिय तमिल हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के चौथे भाग 'कंचना 4' के साथ तमिल सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इस मोस्टअवेटेड फिल्म में नोरा मुख्य भूमिका निभाएंगी। नोरा ने 'कंचना 4' चुनने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, जब मुझे यह फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे लगा कि तमिल सिनेमा में डेब्यू के लिए यह एकदम सही प्रोजेक्ट है। इस फ्रेंचाइजी की पहले से ही मजबूत पहचान है और इसकी अनोखी स्क्रिप्ट ने मुझे आकर्षित किया। नोरा फतेही ने आगे बताया, क्राइम-कॉमेडी ड्रामा मडगांव एक्सप्रेस की सफलता के बाद मैं एक और कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थी और इस प्रोजेक्ट के साथ मुझे वही रास्ता नजर आया। मैं इस फिल्म में काम करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। नोरा ने बताया कि तमिल भाषा सीखना आसान नहीं है। फिल्म के लिए तमिल भाषा सीखना चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया, भाषा हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मैंने पहले हिंदी, तेलुगू और मलयालम में भी काम किया है और अब तमिल मेरे लिए सबसे मुश्किल भाषा है और इसमें काम करने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। नोरा फतेही ने यह भी बताया कि वह अपने किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया, मैं अपने लाइन्स की रिहर्सल करने और उच्चारण पर काम करने के लिए अतिरिक्त समय दे रही हूं। इसके लिए खूब प्रैक्टिस करती हूं। सेट पर मिला प्रोत्साहन सबसे बड़ी प्रेरणा रहा। उन्होंने कहा, क्रू को उम्मीद नहीं थी कि मैं कॉमिक सीन में इतनी सहज रहूंगी। ऐसी प्रतिक्रिया मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह संस्कृति और भाषा का सम्मान करने के साथ-साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका है। मुझे टीम का भी काफी सपोर्ट मिलता है। नोरा ने तमिल और बॉलीवुड सिनेमा के अंतर को भी रेखांकित किया। उनके मुताबिक, तमिल सिनेमा कहानी और परफॉर्मेंस पर केंद्रित है, जबकि बॉलीवुड की अपनी भव्यता और एनर्जी है। दोनों इंडस्ट्री से सीखना मेरे लिए रोमांचक अनुभव है।

अक्षरा सिंह ने ग्रीन साड़ी में बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह बेहतरीन अभिनय और अद्भुत स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। इस कड़ी में अक्षरा ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह ग्रीन कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनकी मुस्कान को देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में अक्षरा का आकर्षक लुक, हल्की-सी मुस्कान और स्टाइलिश पोज फैंस को लुभा रहा है। वह साड़ी में अलग-अलग अंदाज में वीडियो शूट करवा रही हैं। कभी वह सामने से चलकर आती दिख रही हैं, तो कभी पेड़ों के पीछे से पोज दे रही हैं। वह अपने पल्लू को हवा में उड़ाते हुए मौसम का मजा लेती हुई भी नजर आ रही हैं। उनका यह लुक न केवल उनकी खूबसूरती को बयां करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे सादगी के साथ-साथ फैशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं।

वीडियो में अक्षरा ने रोमांटिक शॉर्ट फिल्म बम्बलिंग का गाना फाइनली वी मेट ऐड किया है। अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, सच्ची खूबसूरती ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, लोग खुद ही उसे पसंद करने लगते हैं। उनके इस पोस्ट पर फैंस की तेजी से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई फॉलोअर्स तो उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं, तो कई उनके लिखे कैप्शन को दिल से महसूस करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, आपकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलकता है, लेकिन जिस हिम्मत से आप मुस्कुरा रही हैं, वो काबिल-ए-तारीफ है। अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रह चुकी हैं। उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ चुका है। एक समय था जब दोनों का रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता कड़वाहट में बदल गया। अलगाव के बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन में काफी उथल-पुथल मची।

The Bengal Files:

'बिना फिल्म देखे, क्यों हो रहा विरोध?

'द बंगाल फाइल्स' विवाद पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। अब मिथुन चक्रवर्ती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब पहले से तय था। विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर विवाद हो रहा है। बीते दिनों कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर रिलीज के दौरान काफी हंगामा हुआ था। इस मामले पर दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि लोग फिल्म देखें बिना किस बात का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सोची समझी साजिश थी।

अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बातचीत करते हुए कहा, 'सब कुछ पहले से तय था। लेकिन मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था कि बिना ट्रेलर देखे, बिना कुछ देखे, वे इसका विरोध किस लिए कर रहे हैं? सच्चाई का सामना करने के लिए? तो, यही समस्या है। और कुछ नहीं।'

द बंगाल फाइल्स के मेकर्स पर राजनीतिक लोगों ने FIR दर्ज कराई है। इसपर बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, 'बंगाल में एफआईआर कुरमुरा की तरह बांटी जाती है। अगर टीएमसी का कोई भी पुलिस स्टेशन में जाएगा, तो एफआईआर हो जाएगा। ऐसा ही था, तो कोई बात नहीं। अगर एफआईआर हो गई है, विवेक अग्निहोत्री इसका विरोध करेंगे। कोई बात नहीं।'

विरोधियों को दिया जवाब

द बंगाल फाइल्स का विरोध कर रहे लोगों पर अभिनेता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'हर कोई सच्चाई से डरता है। यही बात है।' आगे उन्होंने बोला- 'यह 1947 है, मेरे जन्म से भी पहले का, जिसके बारे में हम नहीं जानते। अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि नोआखली में क्या हुआ था या कलकत्ता के बड़े नरसंहारों के बारे में क्या हुआ था। क्या हुआ था, हमने एक लाइन पढ़ी क्या हुआ? आप सच नहीं जानना चाहते?

'डिंपल भाभी को बचाओ'

एक्ट्रेस के बयान से इंटरनेट पर मचा कोहराम

हाल ही में स्वरा भास्कर ने सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश बताया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इस बार एक्ट्रेस ने सपा सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश बताया है, जिसके बाद से वो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुझाव दे रहे हैं कि वो डिंपल भाभी को बचा लें। स्वरा भास्कर द्वारा सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश बताए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बायसेक्सुअल मुद्दे पर भी टिप्पणी की है। इसी के बाद से नेटिजंस इस मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आगाह कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव को बचाकर रखें। इसके अलावा कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये क्या-क्या देखना पड़ रहा है।

मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज को एक नेता ने भेजा आपत्तिजनक संदेश

हाल ही में मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने एक युवा राजनेता पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है। मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने केरल की एक राजनीतिक पार्टी के एक युवा नेता पर आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी इस घटना की जानकारी दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आइए जानते हैं आखिर एक्ट्रेस ने किस पर और क्या-क्या आरोप लगाए।

'होटल में आने के लिए कहा'

बुधवार के दिन मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने मीडिया से बात की। एक्ट्रेस ने बताया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस राजनेता के संपर्क में आई थी। उसका अनुचित व्यवहार तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार उससे आपत्तिजनक संदेश मिले थे।' आगे एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि उस नेता ने एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक करने की भी पेशकश की और उन्हें वहां आने के लिए कहा। हालांकि, आपको बताते चलें कि अभिनेत्री ने नेता या उनकी पार्टी का नाम बताने से इनकार कर दिया।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत की, लेकिन

अभिनेत्री ने आगे बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने युवा नेता की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की, लेकिन उन सबने इसे नजरअंदाज किया। इसके साथ ही पार्टी के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'उनके बारे में मेरे मन में जो छवि थी, वह चकनाचूर हो गई है। मेरी शिकायत के बाद भी, उन्हें पार्टी में कई प्रमुख पद दिए गए।'

पीड़ित महिलाओं के लिए उठा रहीं आवाज

रिनी एन जॉर्ज ने कहा, 'मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है, मुझे तो बस ये संदेश मिले हैं। लेकिन अपने दोस्तों के माध्यम से मुझे पता चला कि कई अन्य महिलाओं को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूं।

मानद डॉक्टरेट का सम्मान हासिल करने पर बोले हरिहरन-

अरिजीत सिंह को बताया पसंदीदा गायक

गजल की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके गायक हरिहरन को हाल ही में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर का सम्मान मिला है। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। भारतीय संगीत जगत के दिग्गज और गजलों के बादशाह कहे जाने वाले सिंगर हरिहरन को हाल ही में एक बड़ा सम्मान मिला है। कोलकाता स्थित टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर से नवाजा है। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं, जिन्हें इसी उपाधि से सम्मानित किया गया। हरिहरन ने इसे अपने लिए गर्व और सौभाग्य का पल बताया।

सम्मान पर हरिहरन का बयान

मानद डॉक्टरेट मिलने पर सिंगर हरिहरन ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय संगीत जगत के लिए है। उन्होंने इसे अपने सफर का प्रेरणादायक पड़ाव बताया और आने वाली पीढ़ी के कलाकारों से रिक्वेस्ट की कि वो मेहनत और लगन से संगीत साधना करें।

रियाज करने का बताया महत्व

करीब चार दशकों से भारतीय संगीत को अपनी आवाज से समृद्ध कर रहे हरीहरन ने इस मौके पर कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा मेरे लिए गर्व का पल है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार के लिए रियाज बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक, बिना अभ्यास और लगातार सीखने की लगन के कोई भी गायक लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि साधना है और इसकी बारीकियों को समझना हर कलाकार के लिए अनिवार्य है।

अरिजीत सिंह को बताया पसंदीदा गायक

जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा दौर में उनके पसंदीदा गायक कौन हैं, तो उन्होंने बिना झिझक अरिजीत सिंह का नाम लिया। हरिहरन ने माना कि अरिजीत की गायकी में गहराई और भावनाओं की ऐसी सच्चाई है जो उन्हें श्रोताओं के दिलों तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें गायकी के मामले में अरिजीत अच्छे लगते हैं।

पाकिस्तान की टीम की तरह उसका कप्तान भी फिसड्डी, सवालों के घेरे में सलमान आगा की कप्तानी

नई दिल्ली, एजेंसी। एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम का एलान हो चुका है। नौ सितंबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम की कमान सलमान अली आगा को सौंपी है, जिनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर अब तक फ्लॉप ही रहा है। इस टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि पीसीबी ने दोनों को इस प्रारूप की रणनीति से साइडलाइन कर दिया है।

लय से बाहर चल रही टीम

पाकिस्तान के 17 सदस्यीय स्क्वॉड में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। हालांकि, टीम अभी लय से बाहर चल रही है। हाल ही में उन्हें बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने वापसी की और वेस्टइंडीज को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में हराया। हालांकि, टी20 सीरीज की हार का बदला वेस्टइंडीज की टीम ने वनडे सीरीज में जीत के साथ लिया। ऐसे में पाकिस्तान का एशिया कप में सफर कैसा होगा, इस पर चर्चा तेज है।

पाकिस्तान के मुकाबले

पाकिस्तान की टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर से ओमान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद उसका सामना दुबई में भारत से होगा। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान की टीम तीसरा मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी, जो दुबई में ही 17 सितंबर को खेला जाएगा। सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से शुरू होंगे जबकि फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा।

इन आंकड़ों के आधार पर चुना कप्तान?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के टी20 करियर की बात करें तो उनके आंकड़े बिल्कुल भी कप्तानी के लायक नहीं हैं। 20 मुकाबलों में उन्होंने कुल 380 रन बनाए हैं, यानी मुश्किल से औसत 27.1 का रहा है। टी20 जैसे प्रारूप में जहां बल्लेबाजों से 140-150 के स्ट्राइक रेट की उम्मीद की जाती है, वहां आगा मुश्किल से 115.8 के स्ट्राइक रेट को छू सके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी सिर्फ 56 रन ही है। वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो 20 मैचों में उन्होंने सिर्फ चार विकेट झटके हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1/7 का है।

अब कप्तानी पर नजर डालें तो आगा ने 18 मैचों में पाकिस्तान की कमान संभाली, जिसमें नौ जीते और इतने ही हारे। यानी न टीम आगे बढ़ पाई, न कोई स्थिरता आई। उनकी कप्तानी में कोई बड़ा बदलाव या आक्रामक रणनीति नजर नहीं आई। इन आंकड़ों से साफ है कि सलमान अली आगा न बल्लेबाजी में धमाल मचा पाए हैं, न गेंदबाजी में और न ही कप्तानी में कोई करिश्मा दिखा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किन आधारों पर उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया?

पांच खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार की सिफारिश

इनमें 4 पेरिस ओलिंपिक के मेडलिस्ट, वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश का भी नाम

मनु भाकर
शूटिंग
2 ब्रॉन्ज

सरबजोत सिंह
शूटिंग
ब्रॉन्ज

स्वप्निल कुसाले
शूटिंग
ब्रॉन्ज

अमन सहरावत
रेसलिंग
ब्रॉन्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। खेल मंत्रालय ने पांच खिलाड़ियों के नाम पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किए हैं। इनमें चार खिलाड़ी मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले और अमन सहरावत पेरिस ओलिंपिक के मेडलिस्ट हैं। वहीं, एक नाम चेस के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश का है। मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया को यह जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से ये नाम पद्म पुरस्कार समिति के पास भेजे गए हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 मई से 15 सितंबर के बीच करना होता है। पुरस्कार समिति 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के मौके पर पुरस्कारों की घोषणा करती है। पिछले साल पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण और दिग्गज स्पिनर आर अश्विन पद्मश्री मिला था।

मनु-गुकेश समेत 4 प्लेयर्स को खेल रत्न मिला था – 8 महीने पहले 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था।

नीरज-श्रीजेश को पहले मिल चुका है पद्म पुरस्कार

भारत ने पिछले साल अगस्त-सितंबर में आयोजित पेरिस ओलिंपिक गेम्स में 6 मेडल जीते थे। इनमें एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज शामिल रहे। पेरिस में भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को पद्मभूषण मिल चुका है। नीरज चोपड़ा को 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री प्रदान किया था। पद्म पुरस्कार समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 मेंबर शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।

एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत

सरकार ने कहा- मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं, द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने गुरुवार को कहा है- 'मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है।' मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाइलैटरल सीरीज में इंडिया का स्टैंड बरकरार रहेगा। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से एक लेटर साझा किया, इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारत की पॉलिसी बताई गई है। इसके अनुसार, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल इवेंट्स (चाहे भारत में हों या विदेश में) में भारत इंटरनेशनल खेल संस्थाओं के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। भारतीय टीमें और भारतीय खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। यह ठीक वैसा ही है, जैसे भारत में होने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे।

2 दिन पहले 19 अगस्त को बीसीसीआई ने एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद क्रिकेट एशिया कप में भारत के पाकिस्तान से खेलने का विरोध हो रहा है। इस संबंध में सदन में भी सवाल उठा था। पूर्व क्रिकेटर्स की भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था।

इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार के बाद इसे ,श्व में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को,श्व से होगा।

भारत-पाकिस्तान के 3 मुकाबले हो सकते हैं

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हो सकते है। पहला मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

दूसरा मैच- एशिया कप में लीग स्टेज के बाद सुपर-4 राउंड होगा। भारत-पाकिस्तान के सुपर-4 राउंड में पहुंचने पर 21 सितंबर को भारत-पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत हो सकती है।

तीसरा मैच – अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो 28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा।

क्या पाकिस्तान से खेलना भारत की मजबूरी, बीसीसीआई ने बताए न खेलने के 4 नुकसान

पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत पर बड़ा हमला किया था। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज खेलनी थी। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया। वे पूछते – जो पाकिस्तान हमारा खून बहा रहा है उसके साथ हम क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं? इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से खेल मंत्रालय को निर्देश आता है कि वे बीसीसीआई को कह दें कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी। यह वाकया 2008 का है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 नवंबर को मुंबई में बड़ा हमला किया था। इसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर रोक लगा दी थी। अब सीधा 2025 में लौटते हैं। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पिछले 22 अप्रैल को वहां से आए आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोषों की धर्म पूछकर हत्या कर दी। इसके बाद मांग उठने लगी है कि भारत को अब न सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज बल्कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे मल्टी नेशनल इवेंट में भी पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए। 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप होना है। भारतीय टीम घोषित हो गई है और इस टूर्नामेंट में तीन भारत-पाकिस्तान मैच संभव हैं। पाकिस्तान से खेलने या न खेलने पर सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, बीसीसीआई नहीं चाहता कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान का बायकॉट करे। मीडिया ने इस मुद्दे पर बीसीसीआई के दो शीर्ष अधिकारियों से इसकी वजह पूछी। दोनों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर 4 ऐसे कारण बताए जिनकी वजह से बीसीसीआई अब भी चाहता है कि एशिया कप हो और इसमें भारत-पाकिस्तान मुकाबले भी खेले जाएं...।

रोहित मैदान पर वापसी को बेकरार

इस टीम के खिलाफ जलवा बिखेरते आ सकते हैं नजर

मुंबई, एजेंसी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब टीम इंडिया को दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा की नीली जर्सी में वापसी का बेसब्री से इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से रोहित शर्मा ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। लेकिन अब उनकी टीम इंडिया में वापसी की संभावना ऑस्ट्रेलिया दौरे (19 अक्टूबर से) के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि, रोहित शर्मा इस दौरे से पहले ही एक खास सीरीज में हिस्सा लेने की इच्छा जता चुके हैं, जो कानपुर में खेली जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ खेलने की इच्छा

टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें भारतीय टीम 3 वनडे और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। इस वनडे सीरीज के लिए टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के शामिल होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ कानपुर में होने वाली अनऑफिशियल वनडे सीरीज में खेलने की इच्छा जताई है। ऑस्ट्रेलिया-ए सितंबर में भारत दौरे पर आएगी, जहां वे भारत-ए टीम के साथ दो अनऑफिशियल टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैच लखनऊ में आयोजित होंगे, जबकि तीनों वनडे मैच कानपुर में खेले जाएंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलेंगे रोहित

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रोहित शर्मा इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज में खेलने के इच्छुक हैं ताकि वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। इसके अलावा खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज उनके वनडे करियर की आखिरी सीरीज हो सकती है। बीसीसीआई रोहित को दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, ताकि वे वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखें।

वनडे में रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। अब तक उन्होंने 273 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 265 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए हैं। इसमें उनके 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है, जो वनडे इतिहास के सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर में से एक है।

रेड्डी ने विराट के साथ बिताए अपने खास पल का किया खुलासा

नितीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें टी20 और टेस्ट कैप मिल गई। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया में इस ऑलराउंडर ने विराट कोहली के साथ खेला, जो अंतत: दिल्ली के इस महान बल्लेबाज की आखिरी टेस्ट सीरीज साबित हुई। नितीश रेड्डी को विराट कोहली से अपनी पहली टेस्ट कैप मिली और अब आंध्र प्रीमियर लीग के दौरान एक साक्षात्कार में नितीश रेड्डी ने कहा कि यह उनके आदर्श के साथ उनका सबसे खास पल है। भीमावरम बुल्स के कप्तान भी विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उन्होंने एडिलेड में अपना आखिरी टेस्ट शतक बनाया था और इसे एक और खास पल बताया। क्रके दौरान उन्होंने कहा, विराट भैया ने मुझे जो टेस्ट डेब्यू कैप दी थी, वह मेरे लिए एक बेहद खास पल था और एक और खास पल, विराट भैया का आखिरी टेस्ट शतक मैं उन्हें देखने के लिए नॉन-स्ट्राइकर एंड पर मौजूद था। इस तरह नितीश रेड्डी ने एक बार फिर विराट कोहली के प्रति अपने प्यार का इजहार किया है। इससे पहले भी इस ऑलराउंडर ने विराट कोहली के प्रति अपने लगाव का इजहार किया है और कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान और आरसीबी सुपरस्टार के साथ खेलना उनका सपना था। नितीश रेड्डी अब उम्मीद कर रहे होंगे कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अच्छी शुरुआत को आगे बढ़ाएं और लंबे समय तक देश की सेवा करें। वह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोटिल हो गए।

आईसीसी ने रैंकिंग में हुई गलती पर सफाई दी, बोला- गलती की जांच हो रही

यूएई(एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस?िल (आईसीसी) ने बुधवार (20 अगस्त) को खिलाड़ियों की रैंकिंग अपडेट की, लेकिन इसमें एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। वनडे रैंकिंग में रोहि?त शर्मा और विराट कोहली के नाम गायब थे। पिछले हफ्ते 13 अगस्त को जारी रैंकिंग में दोनों भारतीय बल्लेबाज टॉप-5 में शामिल थे। हालांकि, आईसीसी ने चार घंटे बाद ही गलती में सुधार किया और रैंकिंग अपडेट कर दी। अब आईसीसी ने इस मामले में सफाई दी है।

एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को मिली कप्तानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को चीन के हांगझोउ में पांच से 14 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए बृहस्पतिवार को 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बरकरार रखा गया। यह टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विजेता 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा। भारत को पूल बी में रखा गया है जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा।

टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी और फिर छह सितंबर को जापान से भिड़ेगी। भारत अपना अंतिम पूल मैच आठ सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा। हॉकी इंडिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, 'हांगझोउ में होने वाले महिला एशिया कप के लिए हमने जो टीम चुनी है उसे लेकर हम उत्साहित हैं।

सलीमा पिछले साल कप्तान नियुक्त होने के बाद से टीम का अभिन्न अंग रही हैं। हरेंद्र ने कहा, 'यह टीम कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है और हमने अनुभवी खिलाड़ियों तथा युवा प्रतिभाओं के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, 'हमारा ध्यान आक्रामक और अनुशासित हॉकी खेलने पर होगा और

हमारा मानना ??है कि यह टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ मजबूती से मुकाबला करने की क्षमता रखती है।

टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण है जिसमें गोलकीपिंग की जिम्मेदारी बंसारी सोलंकी और बिचु देवी खारीबाम पर होगी। रक्षा पंक्ति में निक्की प्रधान और उदिता जैसी अनुभवी खिलाड़ी होंगी जिनका साथ युवा मनीषा चौहान, ज्योति, सुमन देवी थोडम और इशिका चौधरी देंगी। मिडफील्ड में नेहा, सलीमा, लालरेमसियामी, शर्मिला देवी, सुनेलिटा टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के जैसी मजबूत खिलाड़ी हैं।

अग्रिम पंक्ति में अनुभवी और उभरते सितारों का मिश्रण है जिसमें नवनीत कौर, संगीता कुमारी, मुमताज खान, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग और रुतजा दादासो पिसल शामिल हैं।

महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर – बंसारी सोलंकी, बिचु देवी खारीबाम

डिफेंडर – मनीषा चौहान, उदिता, ज्योति, सुमन देवी थोडम, निक्की प्रधान, इशिका चौधरी

मिडफील्डर –नेहा, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, सलीमा टेटे, शर्मिला देवी, लालरेमसियामी, सुनेलिटा टोप्पो

फारवर्ड – नवनीत कौर, रुतजा दादासो पिसल, ब्यूटी डुंगडुंग, मुमताज खान, दीपिका और संगीता कुमारी।

बेगूसराय को मिला विकास का नया तोहफ़ा

-प्रधानमंत्री ने किया 6 लेन औंटा-सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन

गयाजी। बेगूसराय का ऐतिहासिक दिन उस समय दर्ज हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने 6 लेन औंटा-सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। बिहार के इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री के साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।

पुल पर पीएम की उपस्थिति और अभिवादन

उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री खुद पुल पर पहुंचे और वहां घूमकर लोगों का अभिवादन किया। जैसे ही उन्होंने अपने गले से गमछा निकाला और हाथ से घुमाकर लोगों का स्वागत किया, माहौल देशभक्ति और उत्साह से भर गया। पुल के दोनों ओर और नीचे घाटों पर भारी भीड़ पीएम को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। लोगों ने हाथ हिलाकर और नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। करीब 37 मिनट तक पीएम इस पुल पर रुके और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत

पुल के नीचे बने घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने बिहार की परंपरा और संस्कृति को मंच पर उतारकर उत्सव जैसा माहौल बना दिया। ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों की गूंज के बीच पूरा क्षेत्र उत्सवधर्मी हो गया। प्रधानमंत्री ने भी इन प्रस्तुतियों को देखा और कलाकारों की हौसलाअफ़ज़ाई की।

राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी

इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। दोनों नेताओं ने पुल का निरीक्षण किया और लोगों की भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद भी हैं, विशेष रूप से उत्साहित नजर आए। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर बारीक नजर रखी।

पुल की अहमियत

औंटा-सिमरिया ब्रिज गंगा नदी पर बना एक 6 लेन का आधुनिक पुल है। यह बिहार में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक अहम मार्ग बनेगा। इस पुल से न सिर्फ बेगूसराय, बल्कि पूरे मिथिलांचल और मगध क्षेत्र को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पुल के शुरू होने से पटना और बेगूसराय के बीच यात्रा का समय काफी घट जाएगा। मालवाहन ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पुल पूर्वांचल और कोसी-सीमांचल क्षेत्र के विकास की नई राह खोलेगा।

लोगों का उत्साह और भीड़

गंगा घाटों पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर थे। जब पीएम ने गमछा लहराकर अभिवादन किया तो भीड़ ने नारेबाजी और तालियों से स्वागत किया। यह दृश्य किसी बड़े पर्व या उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था।

विकास का नया अध्याय

इस पुल का उद्घाटन बिहार में विकास की नई इबारत लिखेगा। औद्योगिक दृष्टिकोण से बेगूसराय को पहले ही "बिहार का पेट्रो-केमिकल हब" कहा जाता है। अब बेहतर कनेक्टिविटी से यहां निवेश और उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विकास की किरण पहुंचेगी। बेगूसराय का यह दिन बिहार की जनता के लिए यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनता से सीधा संवाद किया और पुल पर घूमकर लोगों के साथ जुड़ाव दिखाया, उसने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। औंटा-सिमरिया ब्रिज न केवल यातायात का साधन होगा, बल्कि यह बिहार की प्रगति और कनेक्टिविटी का प्रतीक भी बनेगा।

बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त

-हटाए गए नाम अब ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे

पटना/नई दिल्ली। बिहार में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसी प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम गलती से वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उन्हें दोबारा अपना नाम जुड़वाने के लिए केवल ऑफलाइन ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिले। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों वोटरों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अक्सर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक मतदाता सूची से नाम गायब होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि मतदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होनी चाहिए।

आधार समेत 11 दस्तावेज़ मान्य

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज़ माना जाए। इसके अलावा फॉर्म 6 में दिए गए अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, बिजली-पानी का बिल, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। यानी अब आधार के साथ-साथ कोई भी वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करके मतदाता सूची में नाम जोड़वाना संभव होगा। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कई चुनावों में यह विवाद उठा कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काट दिए जाते हैं और दोबारा जुड़वाने में लोगों को भारी दिक़्क़त होती है।

राजनीतिक दलों पर कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों को भी कठघरे में खड़ा किया। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की – "राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियां ही यहां मौजूद हैं। मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं?" कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब राजनीतिक दलों के पास करीब 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट मौजूद हैं, तो फिर उनकी तरफ से केवल दो ही आपत्तियां क्यों आईं। इसका मतलब है कि पार्टियां मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही हैं।

वोटर लिस्ट और लोकतंत्र

भारत जैसे लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद जरूरी है। यदि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो कोई भी नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची में किसी भी नागरिक का नाम गलत तरीके से नहीं हटना चाहिए। चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का संधारण करे। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि चुनाव केवल आयोग का काम नहीं है, बल्कि इसमें सभी दलों और जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

ऑनलाइन आवेदन क्यों ज़रूरी?

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कई कारणों से अहम है— समय की बचत: मतदाताओं को बार-बार ब्लॉक या बूथ स्तर पर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पारदर्शिता: ऑनलाइन आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। समावेशिता: प्रवासी मजदूर, छात्र और नौकरीपेशा लोग जो अपने गृह जनपद से बाहर रहते हैं, वे भी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तकनीकी पारदर्शिता: डिजिटल रिकार्ड रहने से विवाद कम होंगे और नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया पर निगरानी आसान होगी।

सुप्रीम कोर्ट का संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि नागरिक को यह भरोसा ही न हो कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ चुनाव आयोग पर ही बोझ डालना सही नहीं है, राजनीतिक दलों को भी आगे आना होगा। मतदाता वही हैं, जिनकी बदौलत दल सत्ता में आते हैं। ऐसे में उनकी मदद करना केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

अगली सुनवाई और संभावित असर

इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। माना जा रहा है कि तब तक चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को यह बताएगा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी और किन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी सुविधा मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नसबंदी-टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएं आवारा कुत्ते

-खूंखार और रेबीज संक्रमित रहेंगे कैद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर लंबे समय से चल रही बहस और विवाद पर शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को बिना वजह कैद करना या उन्हें हमेशा के लिए शेल्टर होम में रखना न तो व्यावहारिक है और न ही मानवीय। बल्कि उनका सही समाधान नसबंदी और टीकाकरण है। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी पहले नसबंदी और टीकाकरण किया जाए और फिर उन्हें वहीं छोड़ा जाए, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, खूंखार या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार का खतरा न हो।

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना न खिलाया जाए। यह व्यवस्था दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगी। इसके लिए स्थानीय निकायों और नगर निगमों को अलग से जगह तय करने को कहा गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति पार्क, सड़क या कॉलोनी की गलियों में कुत्तों को खाना नहीं दे सकेगा।

पहले के आदेश को बताया कठोर

इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवासीय इलाकों से आठ हफ्तों में आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम भेजा जाए। कोर्ट की मौजूदा स्पेशल बेंच ने उस आदेश को बेहद कठोर और अव्यावहारिक बताया। बेंच ने कहा कि ऐसा आदेश लागू करना न तो आसान है और न ही यह संविधान में निहित पशु-अधिकारों के अनुरूप है। आवारा कुत्तों को पूरी तरह से शहरी जीवन से बाहर करना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं।

याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका लगाने वालों पर भी जुर्माना लगाया। आदेश में कहा गया कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए और याचिका में शामिल NGO को 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने होंगे। यह कदम कोर्ट ने यह संकेत देने के लिए उठाया कि जनहित याचिकाओं के नाम पर अनावश्यक या कठोर फैसले थोपने की कोशिश स्वीकार्य नहीं।

स्पेशल बेंच का गठन और सुनवाई

यह मामला देशभर में तेजी से चर्चा में आया था क्योंकि आवारा कुत्तों को लेकर आम जनता और डॉग लवर्स के बीच गहरा मतभेद है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच गठित की। 14 अगस्त को इस बेंच ने डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई की और सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो अब सुनाया गया है।

क्यों अहम है यह फैसला?

भारत में आवारा कुत्तों की संख्या करोड़ों में है। अक्सर रेबीज और कुत्तों के काटने के मामले सामने आते रहते हैं। कई राज्यों में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का गंभीर मुद्दा बन चुका है।

भारत पर ट्रम्प सलाहकार का आरोप: रूसी तेल से मुनाफाखोरी, टैरिफ की धमकी

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद-फरोख्त के ज़रिए मुनाफाखोरी कर रहा है। नवारो का कहना है कि भारतीय कंपनियां रूस से बेहद सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं और उसे रिफाइन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में महंगे दाम पर बेच रही हैं। इससे एक तरफ रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक मदद मिल रही है और दूसरी ओर भारत भारी मुनाफा कमा रहा है।

आरोप का मूल संदर्भ

नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर पश्चिमी देशों की प्रतिबंध नीति को कमजोर कर रहा है। उनका दावा है कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी और पश्चिमी देशों को सामान बेचकर जो विदेशी मुद्रा हासिल करती हैं, उसी से रूस से तेल खरीदती हैं। यह प्रक्रिया अमेरिका के हितों को चोट पहुँचाती है क्योंकि इससे न केवल रूस को आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि भारत का वाणिज्यिक फायदा भी बढ़ता है। उनके मुताबिक, इस 'मुनाफाखोरी' के चलते अमेरिका को अपनी घरेलू कंपनियों की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में संतुलन बनाए रखने के लिए टैरिफ लगाना अनिवार्य हो गया है।

भारत की भूमिका पर वैश्विक नजर

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें तेल और गैस की खरीद पर रोक भी शामिल है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक ज़रूरतों का हवाला देते हुए रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी। भारतीय रिफाइनरियां इस तेल को रिफाइन कर एशिया, यूरोप और अफ्रीकी बाज़ारों में बेच रही हैं। इस प्रक्रिया से भारत के चालू खाता घाटे (CAD) पर दबाव कम हुआ और पेट्रोल-डीज़ल जैसी घरेलू ज़रूरतें भी कम दाम पर पूरी हुईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का 'स्मार्ट मैनेजमेंट' है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए आर्थिक मजबूरी भी है, क्योंकि ऊर्जा आयात पर होने वाला खर्च सीधे महंगाई और विकास दर को प्रभावित करता है।

अमेरिका की चिंता क्यों?

अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह यूक्रेन युद्ध लंबा न खींच सके। लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देश रूस से तेल खरीदते रहे हैं, जिससे रूस की आय बनी हुई है। यही वजह है कि अमेरिकी नीति-निर्माता भारत की इस भूमिका को संदेह की नजर से देखते हैं। पीटर नवारो ने कहा, "भारत रूसी तेल से केवल मुनाफा नहीं कमा रहा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से रूस को युद्ध की फंडिंग में मदद भी कर रहा है। जब वे हमें सामान बेचकर पैसे कमाते हैं और उन्हीं पैसों से रूस से तेल खरीदते हैं, तो यह दोहरी चोट है—एक हमारी अर्थव्यवस्था को और दूसरी वैश्विक शांति को।"

टैरिफ की धमकी

नवारो का यह भी कहना है कि अमेरिकी प्रशासन भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है, खासकर आईटी सेवाओं, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में। भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि, नवारो ने यह भी जोड़ा कि "जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है।" उनका संकेत था कि भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक संभावित 'मध्यस्थ' की भूमिका निभा सकता है।

भारत का पक्ष

भारत बार-बार कहता रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत किसी भी देश से अपनी जनता के हित में ऊर्जा खरीदेगा और पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय करेगा। भारत का तर्क यह भी है कि पश्चिमी देश खुद रूस से गैस और कोयले की खरीद जारी रखते हैं, ऐसे में केवल भारत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इसके अलावा, भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच संवाद स्थापित करने और युद्धविराम की अपील करने में भी कई बार सक्रिय भूमिका निभाई है।

भू-राजनीतिक संकेत

नवारो का बयान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है। ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में "अमेरिका फर्स्ट" का एजेंडा हमेशा से रहा है। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाज़ार को दबाव में लाकर अमेरिकी उद्योगों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा करना भी इस बयान के पीछे की रणनीति हो सकती है। पीटर नवारो के इस बयान ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नई बहस को जन्म दिया है। जहां एक ओर अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर रूस से उसकी नजदीकी कम करना चाहता है, वहीं भारत अपने हितों से समझौता करने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में भारत पर टैरिफ लगाता है या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए किसी मध्य मार्ग की तलाश की जाती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत रखे। वहीं, अमेरिका के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत जैसे विकासशील देश की प्राथमिकताएं अलग हैं और वैश्विक शांति के लिए उसके सहयोग को 'दबाव' से ज्यादा 'साझेदारी' की जरूरत है।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार

-सरकारी पैसे से निजी लंदन यात्रा का आरोप

कोलंबो (एजेंसी)। श्रीलंका इन दिनों एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का गवाह बन रहा है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन की यात्रा सरकारी पैसे से की, जबकि यह यात्रा पूरी तरह से निजी थी।

निजी कार्यक्रम पर सरकारी खर्च

पुलिस के अनुसार, उस समय रानिल विक्रमसिंघे क्यूबा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे। इन यात्राओं के पूरा होने के बाद वे सीधे ब्रिटेन चले गए और अपनी पत्नी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यह यात्रा आधिकारिक नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी दौरे के रूप में दिखाया गया और पूरा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस यात्रा में 10 लोगों का समूह शामिल था। कुल खर्च लगभग 1.69 करोड़ रुपए (स्थानीय मुद्रा में करोड़ों रुपए) आया। यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष और सिविल सोसाइटी ने सरकार और पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।

निजी बॉडीगार्ड पर भी आरोप

इतना ही नहीं, विक्रमसिंघे पर एक और गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अपने निजी बॉडीगार्ड को भी सरकारी खजाने से वेतन दिलवाया। सामान्यतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खर्च राज्य वहन करता है, लेकिन निजी सुरक्षाकर्मी को सरकारी कर्मचारी की तरह सैलरी देना नियमों का उल्लंघन है।

गिरफ्तारी का असर

रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी श्रीलंका की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम मानी जा रही है। एक ओर यह घटना भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सख्ती के रूप में देखी जा रही है। दूसरी ओर, विक्रमसिंघे के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष उनकी लोकप्रियता और पुराने नेटवर्क से डरता है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

श्रीलंका में भ्रष्टाचार और जनता का गुस्सा

श्रीलंका पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ईंधन और दवाओं की किल्लत,

महंगाई और बेरोजगारी

इन हालातों ने जनता को पहले ही सरकार और नेताओं के खिलाफ नाराज़ कर रखा है। ऐसे में यदि यह साबित होता है कि एक राष्ट्रपति ने निजी यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए, तो यह जनता के गुस्से को और भड़का सकता है।

रानिल विक्रमसिंघे की पृष्ठभूमि

रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे हैं। वे कई बार प्रधानमंत्री बने। जुलाई 2022 में जनता के भारी विरोध और गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद वे राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल लगातार विवादों से घिरा रहा। हालांकि, उन्हें देश को स्थिरता की ओर ले जाने वाला नेता भी माना गया, क्योंकि उन्होंने IMF से बेलआउट पैकेज लेकर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की थी।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह

गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अगर आरोप साबित होते हैं, तो विक्रमसिंघे को जेल की सजा और राजनीतिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे खुद को निर्दोष साबित कर देते हैं, तो यह उनकी साख को मजबूत करेगा और समर्थकों को एकजुट करेगा। रानिल विक्रमसिंघे का मामला श्रीलंका के लिए कानून और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा है। यह सवाल उठाता है कि क्या सत्ता में बैठे नेता अपने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ उठाते रहे हैं? आज श्रीलंका की जनता पारदर्शिता और ईमानदार शासन चाहती है। यदि पूर्व राष्ट्रपति पर लगे आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न केवल विक्रमसिंघे की साख को खत्म करेगा, बल्कि देश में अन्य नेताओं के लिए भी सबक बनेगा कि सत्ता जनसेवा के लिए है, निजी ऐशो-आराम के लिए नहीं। रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का कानूनी मामला नहीं है, बल्कि यह श्रीलंका की राजनीति और जनता के भरोसे से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से श्रीलंका में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। जनता ने कई बार सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगा है। 2022 का जनआंदोलन इसका ताज़ा उदाहरण है, जब लाखों लोगों ने गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन किए और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। विक्रमसिंघे उन्हीं हालातों में राष्ट्रपति बने थे और उनसे पारदर्शिता व सुधार की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब उन्हीं पर निजी स्वार्थ में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप जनता के गुस्से को और बढ़ा सकता है। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियां इस गिरफ्तारी को अपने लिए राजनीतिक अवसर मान रही हैं। वे इसे जनता के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता साबित करने का मौका समझ रही हैं। दूसरी ओर, विक्रमसिंघे के समर्थक लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि उन्हें राजनीति में किनारे करने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है।

इजराइल की चेतावनी: गाजा सिटी को राफा की तरह मलबे में बदलने की धमकी

-जंग रोकने के लिए 5 शर्तें रखीं

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शुक्रवार को गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी। उनका कहना है कि अगर हमास इजराइल की शर्तों को नहीं मानता, तो गाजा का हाल भी राफा और बैत हनून की तरह किया जाएगा, जो पहले ही मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही उन्होंने गाजा सिटी पर कब्ज़े के लिए इजराइली सेना को अनुमति दे दी थी।

गाजा पर कब्ज़े का ऐलान और सोशल मीडिया संदेश

रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि "गाजा का हाल राफा और बैत हनून जैसा होगा, ठीक वैसा ही जैसा मैंने वादा किया था।" इस संदेश के साथ ही उन्होंने इशारा कर दिया कि इजराइल अब अपने सैन्य अभियान को और ज्यादा आक्रामक बनाने की तैयारी में है। राफा और बैत हनून पहले ही बड़े पैमाने पर तबाही झेल चुके हैं और वहां मानवीय संकट गहराया हुआ है।

जंग रोकने के लिए इजराइल की 5 शर्तें

इजराइल ने युद्धविराम और गाजा में स्थायी शांति के लिए पांच कड़ी शर्तें रखी हैं:

हमास पूरी तरह हथियार डाले।

बचे हुए सभी इजराइली कैदियों की एक साथ रिहाई हो।

गाजा से सभी सैन्य ताकतों का खात्मा हो।

गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण इजराइल के हाथ में रहे।

गाजा में ऐसा नागरिक प्रशासन बने जो न हमास हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण। इन शर्तों से साफ है कि इजराइल गाजा पर राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।

गाजा के लिए मायने

गाजा सिटी फिलिस्तीन का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला इलाका है। अगर यहां बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई होती है तो लाखों निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। पहले ही गाजा पट्टी में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय बार-बार मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील कर रहा है। इजराइल की यह धमकी हालात को और भी भयावह बना सकती है।

हमास और इजराइल के बीच गतिरोध

हमास का कहना है कि वह इजराइल की शर्तों को पूरी तरह नहीं मान सकता, क्योंकि इसका मतलब गाजा पर इजराइल का स्थायी कब्ज़ा होगा। वहीं इजराइल का रुख बेहद सख्त है और वह अब किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहा। इजराइल की नजर गाजा से हमास के पूरी तरह सफाए पर है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। कई देशों ने चेतावनी दी है कि गाजा सिटी पर बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई से मानवीय संकट और गहरा जाएगा। लेकिन इजराइल का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गाजा सिटी को राफा और बैत हनून की तरह मलबे में बदलने की चेतावनी दी है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,